नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 196, नई दिल्ली, बुधवार 21 अक्टूबर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"सफलता केवल मंज़िल पाने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का नाम है।"

02 रात में बालों को खुला रखें, जुड़ा बनाएं या चोटी बनाकर सोएं?

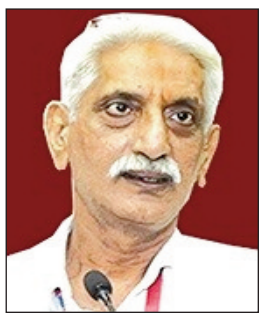
06 पारंपरिक परीक्षाओं से आगे: प्रश्नपत्र लीक-मुक्त परीक्षा प्रणाली का निर्माण

08 राज्यपाल एवं रक्षा राज्य मंत्री के उपस्थिति में मना रांची में रावण दहन कार्यक्रम

दिल्ली ई-रिक्शा नई ड्राफ्ट पॉलिसी 2026 - वादा या फिर कागज़ी कार्रवाई ?

2.5 लाख की सीमा, ECC की अनिवार्यता और प्रवर्तन की पुरानी चुनौती, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 30 दिन में मांगे सुझाव, पर जमीन पर अमल कौन कराएगा ?

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 30 दिन में मांगे सुझाव, पर जमीन पर अमल कौन कराएगा ?



संजय कुमार बाठला - प्रधान संपादक — परिवहन विशेष समाचार पत्र





- सवारी सीमा: चालक के अलावा अधिकतम 4 यात्री, 40 किग्रा तक सामान, खड़े होकर यात्रा और चालक सीट पर बैठना प्रतिबंधित
- मानवीय दायित्व: बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को चढ़ने-उतरने में मदद अनिवार्य
- पार्किंग/संचालन: प्रतिबंधित सड़कों पर संचालन नहीं, पार्किंग ऐसी जगह जहां यातायात बाधित न हो, वाहन पर मालिक का नाम-पता-संपर्क नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य
- दंड: उल्लंघन पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान

2. पूर्व नीति बनाम नई ड्राफ्ट पॉलिसी — तुलनात्मक विश्लेषण

विषय	पूर्व में स्थिति (2015 के बाद की व्यवस्था)	नई ड्राफ्ट पॉलिसी 2026
संख्या सीमा	कोई प्रभावी कैप नहीं, रजिस्ट्रेशन अनियंत्रित बढ़ा	2.5 लाख की अधिकतम सीमा प्रस्तावित
मालिकाना हक	एक व्यक्ति के नाम पर दर्जनों वाहन, किराए पर चलाने की प्रवृत्ति	व्यक्ति के लिए 5, कंपनी के लिए 100 की सीमा
निवास शर्त	बाहर के राज्यों के वाहनों का दिल्ली में संचालन आम	नए मालिक के लिए दिल्ली निवासी अनिवार्य
ECC / अनुपालन	रजिस्ट्रेशन ही काफी माना जाता था, ECC की जांच नगण्य	ECC अनिवार्य, 2 साल की वैधता, बिना ECC संचालन अवैध
चालक लाइसेंस	बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस, बिना बैज चालक	लाइसेंस + PSV बैज अनिवार्य, एक चालक - एक ECC
सवारी क्षमता	6-7 यात्री तक ओवरलोडिंग आम, दुर्घटना का कारण	4 यात्री + 40 किग्रा की स्पष्ट सीमा
एग्रीगेटर	कोई नियंत्रण नहीं	25+ वाहनों पर एग्रीगेटर लाइसेंस अनिवार्य
पार्किंग/रूट	मेट्रो स्टेशन, बाजार, मुख्य सड़कों पर अवैध कब्जाप्रतिबंधित सड़कें तय, व्यवस्थित पार्किंग का नियम	
पारदर्शिता	मालिक की पहचान अक्सर अज्ञात	वाहन पर नाम-पता-संपर्क प्रदर्शन अनिवार्य

निष्कर्ष: पूर्व नीति नियम बनाने तक सीमित रही, नई नीति नियम को बांधने का प्रयास करती है। पर फर्क पॉलिसी के कागज़ में नहीं, प्रवर्तन में आएगा।

3. सबसे बड़ा सवाल — प्रवर्तन कौन कराएगा ? यह वही दिल्ली है जहां:

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई बार ई-रिक्शा के अनियंत्रित संचालन, ओवरलोडिंग, बिना लाइसेंस संचालन पर सख्त आदेश दिए।
- उपराज्यपाल द्वारा राजपत्रित अधिसूचना जारी होकर भी फाइलों में धूल खाती रही।
- परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा और दिल्ली यातायात पुलिस के पास पर्याप्त स्टाफ, वाहन और तकनीक होने के बावजूद सड़कों पर अमल शून्य दिखाई दिया।

सवाल यह है: जब उच्च न्यायालय के आदेश और राजपत्रित अधिसूचना को ही हवा में उड़ा दिया गया, तो नई ड्राफ्ट पॉलिसी को कौन गंभीरता से लेगा ?

4. अगर अमल नहीं हुआ तो दंड क्या होना चाहिए ? — संपादकीय प्रस्ताव परिवहन विशेष समाचार पत्र की मांग है कि इस पॉलिसी में अधिकारियों और एजेंसियों के लिए भी दंड का प्रावधान अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, केवल चालक-मालिक के लिए नहीं।

प्रस्तावित दंड व्यवस्था:

1. प्रवर्तन अधिकारी के लिए:
- निर्धारित क्षेत्र में अवैध ई-रिक्शा संचालन पाया जाए तो संबंधित प्रवर्तन इंस्पेक्टर/जोन अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच, मासिक रिपोर्ट में दर्ज अवहेलना और वेतनवृद्धि रोकना।
- उच्च न्यायालय/अधिसूचना के आदेशों की अवहेलना पर अवमानना की कार्यवाही के लिए विभाग को स्वतः रेफर करना।

2. यातायात पुलिस के लिए:
- प्रतिबंधित सड़कों पर नियमित संचालन की शिकायतों पर कार्रवाई न करने पर संबंधित थाना/ट्रैफिक सर्कल को जवाबदेह बनाना, 30 दिन में जवाबी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देनी होगी।

3. वाहन मालिक/चालक के लिए:
- पहली बार — भारी जुर्माना + ECC निलंबन 30 दिन
- दूसरी बार — ECC रद्द + वाहन जब्ती + 6 माह तक नया रजिस्ट्रेशन नहीं
- तीसरी बार — स्थायी ब्लैकलिस्टिंग और एग्रीगेटर लाइसेंस रद्द

4. संस्थागत जवाबदेही:
- हर माह परिवहन विभाग को दिल्ली सरकार और जनता के सामने प्रवर्तन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी — कितने चालान, कितने ECC रद्द, कितने वाहन जब्त।
- डिजिटल मॉनिटरिंग — GPS/QR कोड आधारित ECC वेरिफिकेशन अनिवार्य, ताकि सड़क पर जांच 2 मिनट में हो।

बिना अधिकारी जवाबदेही के यह पॉलिसी भी पूर्व पॉलिसियों की तरह कागज़ी घोषणा बनकर रह जाएगी।

5. जनहित में क्या जरूरी है ?
- नीति को अंतिम रूप देने से पहले 30 दिन के सुझाव सिर्फ औपचारिकता न हों, चालकों, यूनियनों, RWAs और यात्रियों की सुनवाई हो।
- मेडिकल और शिक्षा की तरह ई-रिक्शा को भी रोजगार और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी का साधन माना जाए, सिर्फ बोझ नहीं।
- गरीब चालक पर जुर्माने से पहले उसे लाइसेंस, ECC और प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था सरकार करे।

संपादकीय टिप्पणी

दिल्ली को ई-रिक्शा की जरूरत है, पर बेलगाम ई-रिक्शा की नहीं। नीति अच्छी है, नियत पर शक है। अगर सरकार चाहती है कि इस बार फर्क पड़े, तो उसे सबसे पहले अपने ही विभागों पर लगाम लगानी होगी। अन्यथा 2.5 लाख की सीमा भी 5 लाख का जाम बन जाएगी।

2. पूर्व नीति बनाम नई ड्राफ्ट पॉलिसी — तुलनात्मक विश्लेषण

विषय	पूर्व में स्थिति (2015 के बाद की व्यवस्था)	नई ड्राफ्ट पॉलि 2026
संख्या सीमा	कोई प्रभावी कैप नहीं, रजिस्ट्रेशन अनियंत्रित बढ़ा	2.5 लाख की अधिकतम सीम प्रस्तावित
मालिकाना हक	एक व्यक्ति के नाम पर दर्जनों वाहन, किराए पर चलाने की प्रवृत्ति	व्यक्ति के लिए 5 कंपनी के लिए 100 की सीमा
निवास शर्त	बाहर के राज्यों के वाहनों का दिल्ली में संचालन आम	नए मालिक के लिए दिल्ली निवासी अनिवा
ECC / अनुपालन	रजिस्ट्रेशन ही काफी माना जाता था, ECC की जांच नगण्य	ECC अनिवार्य, साल की वैधता, बिना ECC संचालन अवैध
चालक लाइसेंस	बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस, बिना बैज चालक	लाइसेंस + PS बैज अनिवार्य, चालक - एक ECC
सवारी क्षमता	6-7 यात्री तक ओवरलोडिंग आम, दुर्घटना का कारण	4 यात्री + 40 किग्रा की स्पष्ट सीमा
एग्रीगेटर	कोई नियंत्रण नहीं	25+ वाहनों पर एग्रीगेटर लाइसें अनिवार्य
पार्किंग/रूट	मेट्रो स्टेशन, बाजार, मुख्य सड़कों पर अवैध कब्जा	प्रतिबंधित सड़वे तय, व्यवस्थित पार्किंग का निय
पारदर्शिता	मालिक की पहचान अक्सर अज्ञात	वाहन पर नाम-पता-संपर्क प्रदर्शन अनिवार

निष्कर्ष: पूर्व नीति *नियम बनाने* तक सीमित रही, नई नीति *नियम को बांधने* का प्रयास करती है। पर फर्क पॉलिसी के कागज़ में नहीं, **प्रवर्तन में** आएगा।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत की और से जनहित में जनता से सवाल और निवेदन

नेताओं से जनता या जनता से नेता — जनता द्वारा सरकार या सरकार द्वारा जनता

संजय कुमार बाठला

संपादकीय — परिवहन विशेष समाचार पत्र - टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत जब राजनीतिक दल जनता को फ्री का लालच देकर सत्ता पर कब्जा प्राप्त करने लगे और जनता भी अपना हक भूलकर फ्री के लालच में किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता पर बिठाने लगे, तब

> क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत की सबसे बड़ी पीठ — भारत के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा, कम से कम 5 जस्टिस की बेंच द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए?

फ्री देना सरकार का दायित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर फ्री किसे दिया जाना है, यह आज सुनिश्चित करना और उस पर नियम बनवाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा करना अति आवश्यक हो गया है।

राजनीतिक दल सत्ता पर विराजमान होने के लिए जनता के ही द्वारा भारत देश निर्माण के लिए दिए जाने वाले टैक्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने लग गए हैं। जो पैसा देश की प्रगति के लिए खर्च होना चाहिए, वह सत्ता पर कब्जा प्राप्त करने पर बर्बाद किया जा रहा है।

फ्री अवश्य आवश्यक है — पर किसे? सर्वप्रथम अगर फ्री ही कुछ और किसी को देना है तो:



1. सभी 12वीं तक की शिक्षा फ्री करनी चाहिए
2. जनता को सही स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो, इसके लिए सभी चिकित्सालय फ्री कर दिए जाएं
3. देश के दिव्यांगों को फ्री सेवाएं प्रदान की जाएं
4. बिन माँ-पिता के रह रहे बच्चों को फ्री सेवाएं प्रदान की जाएं
5. बुजुर्गों को जिनके सहारे साथ नहीं देते या सहारा नहीं है, उन्हें फ्री सेवाएं प्रदान की जाएं
6. विधवा महिलाओं जिनका और कोई सहारा नहीं है, को फ्री सेवाएं प्रदान की जाएं

सबसे प्रमुख — देश में कुछ अति आवश्यक जरूरतमंद समुदाय के अतिरिक्त अगर सरकार फ्री सेवाओं को दे सकती है तो सिर्फ मेडिकल और शिक्षा ही फ्री सेवाओं में घोषित हो, और वह भी किसी एक समुदाय के लिए नहीं, अपितु पूर्ण भारतीय नागरिकों के लिए।

आज का सच आज का सच किसी से छुपा हुआ नहीं है — ना जनता जनार्दन से और ना ही भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय से — कि कैसे राजनीतिक दल लच्छेदार भाषण और फ्री की घोषणाएं करके सत्ता पर काबिज हो रहे हैं।

अगर सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपने आपको रोक लगवाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, तो कम से कम जनहित जनकल्याण में यह तो आदेश जारी कर ही सकता है कि —

> जो भी राजनीतिक दल या नेता इस प्रकार की फ्री की घोषणा कर सीट पर और सत्ता में आए हैं, वह यह सभी फ्री की की हुई घोषणाएं अपनी संपत्ति या राजनीतिक दल की संपत्ति से करेंगे, ना कि जनता द्वारा देश की प्रगति में लगाए जाने वाले टैक्स से।

अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपना पक्ष स्वयं या टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के जुड़कर रखकर खंडपीठ के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी करने के लिए निवेदन कर देश की प्रगति में सहयोग करें।

परेशान न हों! DL खो गया तो घर बैठे Duplicate DL पाएं....



पर्स में नहीं मिल रहा लाइसेंस? दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, 4 आसान स्टेप में 2-4 हफ्ते में नया DL - परिवहन विशेष जनहित गाइड परिवहन विशेष की जनहित में पूरी जानकारी :- DL खो जाने पर क्या करें और Duplicate DL कैसे प्राप्त करें?

तथ्य 1: घबराएं नहीं, यह आम समस्या है RTO के आंकड़ों के अनुसार हर साल लाखों लोग अपना DL खो देते हैं, चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है। इसका समाधान सरकार ने पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। दलालों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं।

तथ्य २: Duplicate DL पाने के 4 आसान स्टेप - घर बैठे:

STEP 1: FIR / NCR दर्ज करें (सबसे जरूरी)
- सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में या अपने राज्य के पुलिस पोर्टल (जैसे Delhi Police - Lost Report) पर DL खोने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- FIR/NCR में DL नंबर, खोने की जगह और तारीख लिखें।
- FIR की कॉपी PDF में सेव कर लें, यही आपका सबसे बड़ा सबूत है कि DL का कोई गलत इस्तेमाल न करे।
- खर्च: लगभग फ्री।

STEP २: Parivahan Sewa वेबसाइट पर जाएं
- आधिकारिक वेबसाइट: https://parivahan.gov.in या https://sarathi.parivahan.gov.in
- Process: Online Services > Driving Licence Related Services > अपना राज्य चुनें > Apply for Duplicate DL
- अपना पुराना DL नंबर, जन्मतिथि, आधार नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें। यदि DL नंबर याद नहीं तो "Find DL Number" से नाम और जन्मतिथि से निकाल सकते हैं।

STEP ३: जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
- FIR / NCR की कॉपी
- आधार कार्ड (पते के प्रमाण के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर (यदि RTO मांगे)
- पुराना DL का विवरण (यदि उपलब्ध हो)
- सभी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।

STEP 4: शुल्क जमा करें और इंतजार करें
- शुल्क: Duplicate DL के लिए सरकारी शुल्क ₹200 से ₹500 तक (राज्य के अनुसार)। जैसे दिल्ली में ₹500 + स्मार्ट कार्ड फीस, UP में ₹400 के आसपास।
- भुगतान: Debit Card / UPI / Net Banking से ऑनलाइन।
- समय: वेरिफिकेशन के बाद २ से 4 सप्ताह में नया DL आपके आधार से लिंक पते पर डाक से आ जाएगा। कई राज्यों में आप RTO से भी कलेक्ट कर सकते हैं या mParivahan / DigiLocker में डिजिटल DL तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
- ट्रैकिंग: Application Number से Parivahan पोर्टल पर स्टेटस देख सकते हैं। हेल्पलाइन: 1073 (MoRTH)

महत्वपूर्ण सुझाव - परिवहन विशेष की सलाह:
- Duplicate DL पर "DUPLICATE" लिखा होगा, लेकिन यह ओरिजिनल जितना ही वैध है।
- हमेशा DigiLocker और mParivahan App में DL की डिजिटल कॉपी सेव रखें, यह कानूनी रूप से मान्य है और पुलिस चेकिंग में काम आती है।
- बैग में DL रखने की आदत बदलें - एक तय जगह रखें और फोटो खींच कर फोन में रखें।
- किसी भी एजेंट को 4000-6000 देने की जरूरत नहीं, पूरा काम ₹500 के अंदर घर बैठे होता है।

संपादकीय टिप्पणी: "जेब में नहीं मिले तो Parivahan पर मिले" - यही असली समाधान, गुस्सा होने से अच्छा है, 10 मिनट निकाल कर ऑनलाइन आवेदन करें। परेशान न हों, दिए गए तरीके का प्रयोग करें और घर बैठे Duplicate DL प्राप्त करें।

रात में बालों को खुला रखें, जुड़ा बनाएं या चोटी बनाकर सोएं?

सौन्दर्य की देवी शहनाज़ हुसैन से जानें कौन सा तरीका है सबसे अच्छा





रात को बिस्तर पर जाने से पहले हम अक्सर तकिया, चादर और कमरे के तापमान जैसी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन बालों के साथ क्या करना है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते /

बालों की देखभाल दिन में जितनी जरूरी होती है, उतनी ही रात में भी होती है./

दरअसल, जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है और यही समय होता है जब प्रकृतिक तौर पर बालों की ग्रोथ होती है. ऐसे में अगर बालों को गलत तरीके से रखा जाए तो वे खराब हो सकते हैं./

बाल खोलकर सोना और टाइट बांधकर सोना, दोनों ही तरीकों से आपके बालों पर अलग-अलग असर पड़ता है।

अगर आपके लम्बे बाल हैं और आप रात को बालों को खुला छोड़ कर सोती हैं तो यह नुकसान दायक हो सकता है क्योंकि लम्बे बाल रात भर तकिये पर इधर उधर रगड़ते हैं जिससे उनमे टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है / तकिये से बालों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तकिये के ऊपर रेशमी या फिर साटन का कवर चढ़ाना चाहिए। / रेशम में अमीनो एसिड और प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं जो बालों को टूटने, रूखे होने और उलझने से बचाते हैं। यह चेहरे पर नींद की रेखाओं (झुर्रियों) को भी कम करता है जिससे बालों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है/

मलबरी सिल्क या साटन के तकिए के कवर का उपयोग करने से घर्षण कम होता है और बाल कम उलझते हैं /

लंबे बाल सोते वक्त करवट बदलने या सिर हिलाने से गर्दन के नीचे दब सकते हैं या उलझ सकते हैं और एक-दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं , जिससे सुबह उठते समय बाल काफी ज्यादा उलझे हुए और रूखे दिख सकते हैं/

अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको रात को सोने से पहले ढीली सी चोटी बना लेनी चाहिए।

मलबरी सिल्क की बजाय तकिये पर साटन का कबर चढ़ाना बेहतर रहेगा क्योंकि यह बजट फ्रेंडली होता है /

आमतौर पर पॉलिएस्टर से बुना जाता है जिससे रेशम जैसी चमक और चिकनाहट आती है। इसकी सतह भी चिकनी होती है, जिससे बालों और त्वचा पर घर्षण कम होता है। यह रेशम के मुकाबले काफी टिकाऊ होता है और इसे मशीन में आसानी से धोया जा सकता है। लेकिन यह रेशम की तुलना में कम हवादार होता है, इसलिए गर्म रातों में यह थोड़ी गर्मी पैदा कर सकता है।

रेशम या साटन के तकिये के कवर में निवेश करना आपके बालों और त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है, साथ ही इससे आपकी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है

बालों को गूंथ लेने से न तो आपके बाल उलझेंगे और न ही ज्यादा टूटेंगे। लंबे और घने बालों को बांधकर सोने से स्कैल्प भी रिलैक्स रहेगा।

बालों को गूंथ लेने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है और उन्हें टूटने से भी बचाता है. साथ ही ढीली चोटी होने से बाल ठीक तरीके से सांस ले पाते हैं.

लेकिन रात को बालों को ज्यादा टाइट बांधकर न सोएं क्योंकि इससे स्कैल्प पर लगातार खिंचाव पड़ता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर पड़ सकती हैं और बाल झड़ सकते हैं./

अगर आपके बाल छोटे हैं और आप बाल खोलकर सोती हैं, तो यह आरामदायक है।

छोटे बालों को बांधकर सोने से स्कैल्प पर कोई खिंचाव नहीं होता / छोटे बाल आपस में नहीं उलझते / छोटे बालों में हवा लगती है जिससे स्कैल्प को सांस लेने में आसानी होती है और रक्त का संचार बेहतर होता है /

आप अपने बालों की ढीली चोटी बनाकर सो सकते हैं लेकिन चोटी बहुत टाइट न हो.चोटी बनाने के लिए सिल्क या साटन की स्क्रंची का इस्तेमाल करें. इससे अलग आप अपने बालों पर सिल्क या साटन का हेयर कवर लगाकर भी सो सकते हैं. हेयर कवर लगाना सबसे अच्छा तरीका है. इससे बाल उलझते नहीं हैं, बालों में रगड़ कम होती है और अगले दिन भी बाल सिल्की महसूस होते हैं. /

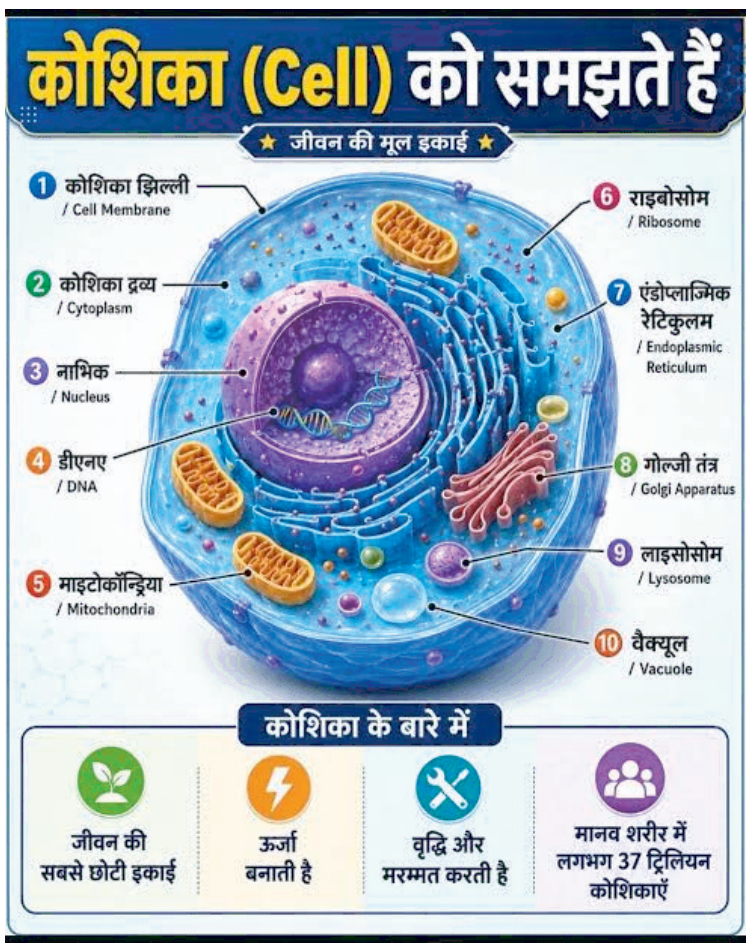
अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, तो रात को हल्का सा हेयर सीरम या नारियल तेल लगाकर सोना फायदेमंद हो सकता है. इससे बाल मॉइस्चराइज रहते हैं और ब्रेकेज कम होता है.

लेखिका अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेष्ज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में लोकप्रिय है

कोशिकाओं की दुनिया: अंगों के निर्माण का रहस्य

डॉ. विजय गर्ग

मानव शरीर एक अद्भुत जैविक प्रणाली है, जो खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। इनमें से प्रत्येक कोशिका जीवन को बनाए रखने के लिए विशिष्ट कार्य करती है। धड़कता हुआ हृदय, ऑक्सीजन का आदान-प्रदान करने वाले फेफड़े, रक्त को छानने वाले गुर्दे और सूचनाओं को संसाधित करने वाला मस्तिष्क—प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट संरचना और भूमिका है। आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी जटिल अंग एक ही निषेचित अंडे से विकसित होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आखिर एक कोशिका से विशेष ऊतकों, अंगों और परस्पर जुड़ी प्रणालियों वाला संपूर्ण जीव कैसे बनता है? इसका उत्तर कोशिका विभाजन, विभेदन, कोशिकाओं के बीच संचार और अंगों के विकास की अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में छिपा है।



एक कोशिका से जटिल जीव तक

मानव जीवन की शुरुआत तब होती है, जब शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलकर एक नई कोशिका बनाता है। इसे युग्मनज (जाइगोट) कहते हैं। इस कोशिका में जीव के विकास के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी मौजूद होती है। बार-बार विभाजन के माध्यम से यह एक से दो, दो से चार, चार से आठ और फिर लगातार अधिक कोशिकाओं में बदलती जाती है। इस प्रारंभिक प्रक्रिया को विदलन (क्लीवेज) कहा जाता है। इस दौरान कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन शुरुआत में विकसित हो रहे भ्रूण का कुल आकार विशेष रूप से नहीं बढ़ता।

विकास के अगले चरण में कोशिकाएँ मिलकर ब्लास्टोसिस्ट नामक संरचना बनाती हैं। इसके आंतरिक कोशिका समूह से भ्रूण का विकास होता है, जबकि अन्य कोशिकाएँ विकास के लिए आवश्यक सहायक संरचनाओं के निर्माण में योगदान देती हैं।

गैस्ट्रुलेशन नामक प्रक्रिया के दौरान कोशिकाएँ पुनर्व्यवस्थित होकर तीन प्राथमिक भ्रूणीय परतें बनाती हैं—एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये परतें विभिन्न ऊतकों और अंगों के निर्माण की नींव रखती हैं।

एक्टोडर्म से मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और त्वचा की बाहरी परत विकसित होती है। मेसोडर्म से मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, रक्त और परिसंचरण तंत्र के अनेक भाग बनते हैं। एंडोडर्म पाचन तथा श्वसन मार्ग की आंतरिक परत बनाता है और यकृत तथा अग्न्याशय जैसे अंगों के विकास में योगदान देता है।

यह समन्वित परिवर्तन अंगों के निर्माण की शुरुआत करता है।

कोशिका विभेदन: जीवन में विशिष्टता का विकास

जीव के विकास की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक कोशिका विभेदन है। शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में मूल रूप से समान डीएनए होने के बावजूद उनके कार्य अलग-अलग होते हैं। तंत्रिका कोशिका विद्युत संकेतों का संचार करती है, मांसपेशी कोशिका संकुचित होती है और लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है।

इन अंतरों का प्रमुख कारण यह है कि विभिन्न कोशिकाओं में जीनों के अलग-अलग समूह सक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। रासायनिक संकेत, नियामक प्रोटीन और पड़ोसी कोशिकाओं के साथ संपर्क यह निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं कि कौन-से जीन सक्रिय होंगे। परिणामस्वरूप, कोशिकाएँ विशिष्ट आकार, संरचना और कार्य प्राप्त करती हैं।

उदाहरण के लिए, विकसित होती मांसपेशी कोशिकाएँ संकुचन के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाती हैं, जबकि अग्न्याशय की विशेष कोशिकाएँ रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का उत्पादन करती हैं।

यह प्रक्रिया अनियमित नहीं होती, बल्कि सुव्यवस्थित जैविक निर्देशों के अनुसार चलती है। इसी कारण कोशिकाएँ विशिष्ट ऊतकों और कार्यशील अंगों का निर्माण कर पाती हैं।

कोशिकाएँ अंगों का निर्माण कैसे करती हैं?

अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को अंगजनन (ऑर्गेनोजेनेसिस) कहा जाता है। इस दौरान विशिष्ट कोशिकाएँ विभाजित होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती हैं, आपस में संकेतों का आदान-प्रदान करती हैं और त्रि-आयामी संरचनाओं में व्यवस्थित होती हैं। विभिन्न ऊतक एक साथ विकसित होकर अंग को कार्य करने योग्य बनाते हैं।

हृदय इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। विकास के प्रारंभिक चरण में कोशिकाएँ एक सरल हृदय नलिका बनाती हैं। समन्वित वृद्धि, मुड़ने और संरचनात्मक बदलावों के माध्यम से यह नलिका धीरे-धीरे विकसित होकर हृदय के कक्षों, वाल्वों और प्रमुख रक्त वाहिकाओं वाली संरचना बन जाती है। हृदय के परिपक्व होने के साथ उसकी विद्युत गतिविधि और मांसपेशियों के संकुचन भी विकसित होते हैं।

इसी प्रकार, फेफड़ों में श्वसन मार्ग बार-बार शाखाओं में विभाजित होता है और अंततः लाखों छोटी वायु थैलियाँ बनती हैं, जिन्हें एल्विओलाई कहते हैं। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान-प्रदान के लिए विशाल सतही क्षेत्र उपलब्ध कराती हैं। गुर्दों में रक्त को छानने वाली विशिष्ट इकाइयाँ विकसित होती हैं, जबकि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स और सहायक कोशिकाओं के जटिल नेटवर्क बनते हैं।

प्रत्येक अंग के सफल निर्माण के लिए सही समय, स्थानिक व्यवस्था और कोशिकाओं के बीच संचार अत्यंत आवश्यक हैं।

कोशिकाओं के बीच संचार की भूमिका

कोशिकाएँ सामान्यतः अलग-थलग रहकर विकसित नहीं होतीं। वे रासायनिक संदेशवाहकों, प्रत्यक्ष संपर्क और अपने आसपास के वातावरण से मिलने वाले संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान करती हैं। ये संकेत निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कोशिकाएँ कहाँ जाएँगी, कब विभाजित होंगी और कौन-सी विशिष्ट भूमिका निभाएँगी।

Wnt, Hedgehog और Notch जैसे संकेत मार्ग विकास की अनेक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका प्रभाव ऊतक के प्रकार, विकास के चरण और अन्य संकेतों के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर निर्भर करता है।

कोशिकाओं के आसपास मौजूद प्रोटीनों और अन्य अणुओं का जाल, जिसे बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स कहा जाता है, संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है और कोशिकाओं के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये सभी तंत्र मिलकर अंगों के उचित आकार और अनुपात को विकसित करने में सहायता करते हैं।

यदि इन संकेतों में गड़बड़ी हो जाए, तो विकास प्रभावित हो सकता है और कभी-कभी जन्मजात विकृतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।

वैज्ञानिक प्रगति और चिकित्सा की संभावनाएँ

अंगों के निर्माण को समझने से पुनर्योजी चिकित्सा (रीजेनेरेटिव मेडिसिन) के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खुली हैं। वैज्ञानिक स्टेम कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जो विभिन्न विशिष्ट कोशिका प्रकारों में विकसित हो सकती हैं। इससे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के संभावित तरीकों को समझने में मदद मिलती है।

ऑर्गेनॉइड स्टेम कोशिकाओं या ऊतकों से प्राप्त कोशिकाओं की सहायता से प्रयोगशाला में विकसित की गई छोटी, त्रि-आयामी संरचनाएँ होती हैं। ये आंत, मस्तिष्क और यकृत जैसे अंगों की कुछ विशेषताओं की नकल कर सकती हैं। इनकी मदद से वैज्ञानिक रोगों का अध्ययन करते हैं, विकास की प्रक्रियाओं को समझते हैं और संभावित उपचारों की जाँच करते हैं।

ऊतक अभियांत्रिकी में कोशिकाओं को सहायक पदार्थों के साथ जोड़कर जैविक संरचनाएँ बनाई जाती हैं, जो भविष्य में क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में उपयोगी हो सकती हैं। हालाँकि, प्रत्यारोपण के लिए पूरी तरह कार्यशील और जटिल अंगों का निर्माण अभी भी विज्ञान के सामने एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष

एक निषेचित अंडे से जटिल मानव शरीर बनने की यात्रा जैविक संगठन की अद्भुत क्षमता को दर्शाती है। कोशिका विभाजन कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है, विभेदन उन्हें विशिष्ट कार्य प्रदान करता है और कोशिकाओं के बीच संचार ऊतकों तथा अंगों के निर्माण में समन्वय स्थापित करता है।

जो प्रक्रिया पहली दृष्टि में प्रकृति का चमत्कार लगती है, वह वैज्ञानिक नियमों और अद्भुत सटीकता का उदाहरण भी है। प्रत्येक अंग असंख्य कोशिकाओं की सामूहिक गतिविधियों का परिणाम है, जो आनुवंशिक निर्देशों और अपने वातावरण से मिलने वाले संकेतों के अनुसार कार्य करती हैं।

कोशिकाओं के विकास के रहस्यों को समझकर वैज्ञानिक न केवल जीवन के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, बल्कि रोगों की पहचान, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और भविष्य के उपचारों के लिए नए रास्ते भी खोल रहे हैं। इसलिए कोशिका केवल जीवन की मूलभूत इकाई नहीं है, बल्कि प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक की शुरुआत भी है।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य | प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब – 152107

बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड और गेहूँ के प्रोटीन पर मंडराता खतरा

डॉ. विजय गर्ग

गेहूँ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। यह अरबों लोगों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी और पोषक तत्व प्रदान करता है। भारत की रोटियों से लेकर दुनिया के अन्य हिस्सों में खाई जाने वाली ब्रेड और पास्ता तक, गेहूँ खाद्य सुरक्षा और मानव पोषण का एक प्रमुख आधार है। लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, जो जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है, एक ऐसी चुनौती पैदा कर रही है जो आसानी से दिखाई नहीं देती। यह चुनौती गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा और उसकी पोषण गुणवत्ता में संभावित कमी से जुड़ी है। यह स्थिति विशेष रूप से उन देशों के लिए चिंता का विषय है, जहाँ गेहूँ लोगों के दैनिक आहार का मुख्य हिस्सा है।

कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा पानी की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कुछ परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा प्रकाश संश्लेषण को तेज कर सकती है और पौधों की वृद्धि में सुधार ला सकती है। इस प्रभाव को अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड का उर्वरक प्रभाव कहा जाता है। यदि पानी और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों, तो इससे फसल की पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन पौधों की अधिक वृद्धि का अर्थ यह आवश्यक नहीं है कि उनकी पोषण गुणवत्ता भी बेहतर हो जाए।

वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा गेहूँ सहित कई महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में प्रोटीन और कुछ खनिजों की सांद्रता को कम कर सकती है। इस प्रभाव की मात्रा गेहूँ की किस्म, खेती की परिस्थितियों, मिट्टी की उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। इसके बावजूद यह एक गंभीर चिंता का विषय है। अधिक उपज वाली फसल के प्रत्येक इकाई भार में प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है। इस प्रकार कुल उत्पादन बढ़ने के बावजूद पोषण संबंधी चुनौती उत्पन्न हो सकती है।

इसका एक कारण कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्वों के अनुपात में बदलाव है। जब पौधे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो उनके दानों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ सकती है। यदि स्टार्च की मात्रा नाइट्रोजनयुक्त यौगिकों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, तो दाने में प्रोटीन का प्रतिशत कम हो सकता है। इसे पोषक तत्वों के तनुकरण का प्रभाव कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड सीधे प्रोटीन को नष्ट कर देती है, बल्कि पौधों की वृद्धि और पोषक तत्वों के वितरण में बदलाव अनाज की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं।

पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गेहूँ मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषित करता है और इसका उपयोग अमीनो अम्लों तथा प्रोटीन के निर्माण में करता है, जो दानों के विकास के लिए आवश्यक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा में पौधे कार्बोहाइड्रेट जमा करने की तुलना में नाइट्रोजन को उसी अनुपात में अवशोषित या उपयोग नहीं कर पाते। इससे दानों में प्रोटीन की सांद्रता कम हो सकती है। हालांकि, प्रत्येक फसल और पर्यावरण में इसका प्रभाव समान नहीं होता। मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता, तापमान, पानी की आपूर्ति और खेती के तरीके भी परिणामों को प्रभावित करते हैं।

इस समस्या का प्रभाव केवल कृषि संबंधी आँकड़ों तक सीमित नहीं है। प्रोटीन शारीरिक विकास, ऊतकों की मरम्मत, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अनेक लोगों के आहार में गेहूँ प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जिनकी दालों, दूध, अंडों, मछली और मांस जैसे विविध पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक सीमित पहुँच है। इसलिए गेहूँ में प्रोटीन की थोड़ी-सी कमी भी उन लोगों को अधिक प्रभावित कर सकती है, जिनके आहार में पहले से ही प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है।

बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार पोषण संबंधी कमियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में दैनिक भोजन का बड़ा हिस्सा गेहूँ से प्राप्त होता है, वहाँ अनाज की गुणवत्ता में गिरावट के कारण पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गेहूँ अचानक खाने योग्य नहीं रहेगा, बल्कि इसकी पोषण संरचना में धीरे-धीरे होने वाले बदलाव पहले से मौजूद जनस्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं।

भारत के लिए इस मुद्दे को गंभीरता से लेना विशेष रूप से आवश्यक है। देश के बड़े हिस्से में गेहूँ मुख्य खाद्य पदार्थ है और लाखों परिवार दैनिक पोषण के लिए गेहूँ से बने खाद्य पदार्थों पर निर्भर हैं। बढ़ता तापमान, वर्षा के बदलते पैटर्न, पानी की कमी और जलवायु से जुड़े अन्य दबाव पहले से ही कृषि उत्पादन को चुनौती दे रहे हैं। यदि बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गेहूँ के दानों में प्रोटीन की सांद्रता भी घटती है, तो देश को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है—फसल की पैदावार बनाए रखना और साथ ही खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता की रक्षा करना। फिर भी यह समझना आवश्यक है कि बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव जटिल हैं। यह कभी-कभी फसलों की वृद्धि और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार कर सकती है, लेकिन गर्मी के तनाव, सूखे, पोषक तत्वों की कमी और चरम मौसमी घटनाओं के कारण ये लाभ कम भी हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन गेहूँ उगाने वाले सभी क्षेत्रों को एक समान प्रभावित नहीं करता। इसलिए वैज्ञानिकों को केवल पैदावार ही नहीं, बल्कि अनाज की पोषण गुणवत्ता का भी मूल्यांकन करना चाहिए। शोधकर्ता और कृषि संस्थान ऐसी गेहूँ की किस्में विकसित करके इस चुनौती का सामना करने में मदद कर सकते हैं, जो बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड और बदलती जलवायु परिस्थितियों में भी प्रोटीन का स्तर बनाए रख सकें। नई किस्में विकसित करते समय पैदावार, प्रोटीन की मात्रा, आवश्यक अमीनो अम्लों, खनिजों तथा गर्मी और सूखे को सहन करने की क्षमता पर ध्यान देना चाहिए। नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, उचित उर्वरक प्रबंधन और कुशल सिंचाई भी अनाज की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, उर्वरकों का उपयोग पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए संतुलित ढंग से किया जाना चाहिए।

कृषि अनुसंधान के साथ-साथ पोषण संबंधी नीतियों में सुधार भी आवश्यक है। दालों, मसूर, दूध और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों से युक्त संतुलित आहार को बढ़ावा देकर किसी एक खाद्य फसल पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सकती है। सरकारी खाद्य वितरण कार्यक्रमों में भी केवल अनाज की मात्रा ही नहीं, बल्कि उसकी पोषण गुणवत्ता को महत्व देना चाहिए। गेहूँ में प्रोटीन और खनिजों की मात्रा की नियमित जाँच से उभरते जोखिमों की पहचान की जा सकती है और समय रहते उचित कदम उठाए जा सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन केवल बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियरों या चरम मौसमी घटनाओं का मुद्दा नहीं है। यह हमारी थाली में पहुँचने वाले भोजन के पोषण मूल्य को भी प्रभावित कर सकता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और गेहूँ के प्रोटीन के बीच संबंध हमें याद दिलाता है कि खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादन की मात्रा के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। भविष्य की चुनौती ऐसी जलवायु-अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित करना है, जो पोषण से समझौता किए बिना बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सरकारों, वैज्ञानिकों, किसानों और उपभोक्ताओं को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, फसलों की बेहतर किस्में विकसित करने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। गेहूँ के भविष्य का मूल्यांकन केवल काटी गई फसल के टनों से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले पोषण से भी किया जाना चाहिए। हमारी दैनिक रोटी को पौष्टिक बनाए रखना एक स्वस्थ और टिकाऊ दुनिया के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

वैज्ञानिक तथ्य: जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (द्वारा उद्धृत एक मेटा-विश्लेषण के अनुसार, लगभग 546–586 पीपीएम कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता में उगाए गए गेहूँ में प्रोटीन की सांद्रता औसतन 6.3 प्रतिशत कम पाई गई। इसके साथ ही लौह और जिंक की मात्रा में भी कमी देखी गई। यह प्रभाव गेहूँ की किस्म और खेती की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

दशहरे के दिन जलेबी खाने और गन्ना (ईख) खरीदने की परंपरा काफी पुरानी और लोकप्रिय



केके छाबड़ा परिवहन विशेष समाचार पत्र

दशहरे के दिन जलेबी खाने और गन्ना (ईख) खरीदने की परंपरा काफी पुरानी और लोकप्रिय है। इसके पीछे धार्मिक कथाएं, मौसमी और वैज्ञानिक कारण, और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हैं:

1. जलेबी खाने का कारण

* भगवान राम की प्रिय मिठाई (शशकुली): प्राचीन मान्यताओं और लोककथाओं के अनुसार, भगवान श्री राम को 'शशकुली' नामक मिठाई अत्यंत प्रिय थी। इसी शशकुली को आज के समय में जलेबी कहा जाता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम की इसी पसंदीदा मिठाई को बांटकर उत्सव मनाया गया था, इसलिए विजयदशमी के दिन जलेबी खाना विजय का प्रतीक बन गया।

* मौसम में बदलाव और स्वास्थ्य: दशहरा आश्विन मास में आता है, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो रही होती है और हल्की ठंड (गुलाबी ठंड) की शुरुआत होती है। आयुर्वेद के अनुसार इस बदलते मौसम में वात और पित्त का संतुलन बिगड़ने से सिरदर्द (माइग्रेन) या कमजोरी की समस्या हो सकती है। सुबह या दिन में गरम जलेबी (विशेषकर दूध या दही के साथ) खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और यह मौसमी बदलाव से तालमेल बिठाने में मदद करती है।

2. गन्ना (ईख) खरीदने का कारण

* नई फसल और समृद्धि का स्वागत: दशहरा खरीफ की फसल की कटाई और रबी की बुवाई के संधिकाल में आता है। इस समय गन्ने की नई फसल तैयार हो रही होती है। हमारे देश में परंपरा रही है कि किसी भी नई फसल का पहला हिस्सा ईश्वर को अर्पित किया जाता है और घर में शुभता के लिए लाया जाता है।

* अहंकार और रावण के पुतले से जुड़ाव: कई ग्रामीण परंपराओं में गन्ने को रावण के पुतले के दहन के बाद 'विजय की निशानी' के रूप में घर ले जाने की रीत है। गन्ना ऊपर से सख्त और मजबूत होता है, लेकिन अंदर से बेहद मीठा। यह संदेश देता है कि कठोर अहंकार को तोड़कर भीतर की मिठास अपनानी चाहिए।

* लक्ष्मी और कामदेव का प्रतीक: हिंदू परंपरा में ईख (गन्ना) को धन, वैभव और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे घर लाना सुख-शांति और संपन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही, बच्चों को चबाकर गन्ना खाने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं।

संक्षेप में, यह परंपरा अधर्म पर धर्म की जीत की मिठास मनाने, नई फसल का स्वागत करने और बदलते मौसम में सेहत को दुरुस्त रखने का एक सुंदर मेल है।



धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

21 अक्टूबर 2026 | दिन का अंक: 5 — बदलाव, संवाद, गति, अनुकूलन और अवसर

मूलांक 1

धन व करियर: दिन का अंक 5 आपकी नेतृत्व ऊर्जा में गति, संवाद और लचीलापन जोड़ता है। नया संपर्क, प्रस्ताव या तेज निर्णय अवसर खोल सकता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से पहले आर्थिक विवरण जांचें।
रिश्ते: आप स्वतंत्रता और तुरंत आगे बढ़ना चाह सकते हैं। साथी या परिवार को अपनी योजना बताते रहें ताकि आत्मविश्वास उपेक्षा जैसा न लगे।
सावधानी: अचानक खर्च, अधीर भाषा और केवल नया आकर्षक लगने के कारण योजना बदलने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक साहसी लेकिन जानकारी पर आधारित कदम लें और अपनी योजना स्पष्ट बताएं।

मूलांक 2

धन व करियर: दिन 5 आपको हिचकिचाहट से बाहर निकलकर अधिक सक्रिय संवाद करने को कहता है। नेटवर्किंग या लचीली साझेदारी मदद कर सकती है, लेकिन केवल सबको खुश रखने के लिए शर्तें स्वीकार न करें।
रिश्ते: दिन की तेज गति आपकी संवेदनशीलता को अस्थिर कर सकती है। सामने वाले की बात का अनुमान लगाने के बजाय प्रश्न पूछें।
सावधानी: भावनात्मक खर्च, अनिर्णय और बहुत सारी राय से उलझने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: लचीले रहें, लेकिन एक स्पष्ट व्यक्तिगत सीमा बनाए रखें।

मूलांक 3

धन व करियर: दिन 5 आपकी अभिव्यक्ति के अनुकूल है और संवाद, बिक्री, शिक्षण या डिजिटल गतिविधि से पहचान ला सकता है। उन्हीं अवसरों पर ध्यान दें जिनमें व्यावहारिक आगे की योजना हो।
रिश्ते: बातचीत जीवंत और आनंददायक रह सकती है। हास्य में सम्मान रखें और हल्के वादों या अस्पष्ट संकेतों से भ्रम न पैदा करें।
सावधानी: बिखरा ध्यान, अनावश्यक सामाजिक खर्च और क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अपने शब्दों से एक अच्छे अवसर को आगे बढ़ाएं।

मूलांक 4

धन व करियर: दिन 5 आपकी स्थिरता पसंद प्रकृति को समझदारी से लचीला बनने को कहता है। समय, तरीका या व्यवसायिक दृष्टिकोण बदलना उपयोगी हो सकता है, यदि मूल आधार सुरक्षित रहे।
रिश्ते: अचानक बदलाव आपको परेशान कर सकता है। अपनी व्यवस्था की जरूरत बताएं, लेकिन दूसरों को बंधा हुआ महसूस न कराएं।
सावधानी: कठोरता, हर बदलाव का विरोध और नियंत्रण वापस पाने के लिए आर्थिक निर्णय से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: आधार स्थिर रखें और एक व्यावहारिक बदलाव स्वीकार करें।

मूलांक 5

धन व करियर: आपके मूलांक 5 और दिन के अंक 5 की ऊर्जा एक-दूसरे को बहुत मजबूत करती है। संवाद, गति, नेटवर्किंग और अनुकूलन क्षमता बढ़ेगी। बिक्री, मीटिंग और नए संपर्क के लिए अच्छा दिन है, लेकिन आवेग में धन संबंधी निर्णय न लें।
रिश्ते: सामाजिक ऊर्जा अधिक रहेगी और विविधता की इच्छा बढ़ सकती है। अपने इरादे स्पष्ट रखें ताकि स्वतंत्रता अस्थिरता न बने।
सावधानी: जोखिमपूर्ण शॉर्टकट, अधिक खर्च, गॉसिप और उत्साह में प्रतिबद्धता से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अपनी गति को एक उच्च-मूल्य अवसर पर केंद्रित करें और उसे पूरा करें।

मूलांक 6

धन व करियर: दिन 5 आपकी आराम पसंद ऊर्जा में गति लाता है। क्लाइंट कार्य, रचनात्मक प्रचार या नई सेवा का विचार लाभ दे सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल के आकर्षण से बजट सुरक्षित रखें।
रिश्ते: आप निकटता और नवीनता दोनों चाह सकते हैं। रिश्ते से बाहर उत्तेजना खोजने के बजाय साथ में कुछ नया और आनंददायक करें।
सावधानी: आराम के लिए खर्च, अधिकार भावना और योजना बदलने पर भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: विविधता जोड़ें, लेकिन आर्थिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें।

मूलांक 7

धन व करियर: दिन 5 आपकी गहरी सोच को संवाद और प्रयोग की ओर ले जाता है। शोध किया हुआ विचार साझा करें, नया तरीका आजमाएं या ऐसे व्यक्ति से जुड़ें जो दृष्टिकोण बढ़ा सके।
रिश्ते: आपको स्पेस चाहिए हो सकती है, जबकि दिन बातचीत को बढ़ाता है। अचानक गायब होने के बजाय अपनी सीमा स्पष्ट बताएं।
सावधानी: अत्यधिक सोच, अचानक दूरी और आजमाए बिना उपयोगी बदलाव नकारने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: तथ्यों पर टिके रहते हुए एक नया तरीका आजमाएं।

मूलांक 8

धन व करियर: दिन 5 आपकी महत्वाकांक्षी ऊर्जा के लिए तेजी से बदलते व्यवसायिक अवसर ला सकता है। बातचीत, नेटवर्किंग और विस्तार देखें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जांचें और तुरंत लाभ के पीछे न भागें।
रिश्ते: आपकी मजबूत प्रकृति सामने वाले की स्वतंत्रता की जरूरत से टकरा सकती है। नियंत्रण के बजाय स्पष्ट अपेक्षा और आपसी सम्मान रखें।
सावधानी: सट्टा निर्णय, प्रभुत्व और धन से दूसरों की पसंद प्रभावित करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: व्यवसायिक रूप से सतर्क, लचीले और अनुशासित—तीनों रहें।

मूलांक 9

धन व करियर: दिन 5 आपकी उद्देश्यपूर्ण और तीव्र ऊर्जा में गति लाता है। नया संपर्क या बदलाव आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीच में न छोड़ें।
रिश्ते: आप पुरानी भावनाओं से आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। अचानक निर्णय लेने के बजाय इस बदलाव को ईमानदारी से समझाएं।
सावधानी: आवेग में उदारता, अचानक संबंध या योजना छोड़ना और भावनात्मक बेचैनी में निर्णय से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: बदलाव स्वीकार करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण वादा पूरा करें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes
Vediccodes - Your vibrations... our solutions

66 वर्षों से मां दुर्गा की आराधना में जुटी काशी दुर्गोत्सव समिति,चार दिनों तक चला प्रसाद वितरण



सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को दी जाएगी विदाई,प्रतिदिन 500 से 1500 श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

(संतोष कुमार सिंह)

वाराणसी :- धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में दुर्गापूजा की परंपरा को जीवंत बनाए रखने में काशी दुर्गोत्सव समिति, चेतसिंह किला,हरिश्चंद्र रोड शिवाला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समिति पिछले 66 वर्षों से मां दुर्गा की आराधना और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जोड़ रही है। नवरात्र के दौरान यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। समिति की ओर से आयोजित भोग एवं प्रसाद वितरण में प्रतिदिन लगभग 500 से 1500 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस वर्ष नवरात्र में एक दिन की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने के कारण सप्तमी,अष्टमी और नवमी के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कुल चार दिनों तक चला इस दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

सिंदूर खेला के साथ होगा मां को विदाई देने का आयोजन

दुर्गापूजा के समापन अवसर पर बुधवार को समिति की ओर से सिंदूर खेला का आयोजन किया जाएगा। इस पारंपरिक आयोजन में महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना करेंगी इसके साथ ही एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा को भावपूर्ण विदाई दी जाएगी। यह आयोजन बंगाली संस्कृति और दुर्गापूजा की परंपराओं का प्रमुख हिस्सा है।

समिति के पदाधिकारी एवं जिम्मेदारियां

काशी दुर्गोत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक कांति चक्रबरती हैं जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी अभिजीत चौधरी संभाल रहे हैं। भोग सेक्रेटरी के रूप में मनीष भट्टाचार्य कानू भट्टाचार्यऔर प्रसून भट्टाचार्य कार्यरत हैं। मीडिया प्रभारी अविनाश भट्टाचार्य तथा स्मारिका प्रभारी (Souvenir In-charge) चैताली भट्टाचार्य ट्रेजरार आशीष दास गुप्ता हैं।

समिति की 66 वर्षों की परंपरा धार्मिक आस्था,सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है हर वर्ष की तरह इस बार भी मां दुर्गा की पूजा- अर्चना और प्रसाद वितरण में श्रद्धालुओं की भागीदारी ने आयोजन को विशेष बना दिया।

205 कोबरा बटालियन मुख्यालय में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हुआ कन्या पूजन



कमांडेंट नरेश पंवार के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में कन्याओं को तिलक लगाकर चुनरी ओढ़ाई गई

परिवहन विशेष न्यूज

गयाजी। 205 कोबरा बटालियन मुख्यालय में नवरात्रि के पावन अवसर पर कमांडेंट नरेश पंवार के निर्देशन में महानवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। इस दौरान विधि-विधान से कन्याओं की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कन्याओं के चरण धोकर की गई। इसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाकर चुनरी ओढ़ाई गई तथा पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना की गई। कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी आराधना की गई। इस अवसर पर कन्याओं को भोजन कराया गया तथा उपहार देकर सम्मानित किया गया।

नवरात्रि के नौवें दिन आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई। कार्यक्रम में बटालियन के अधिकारियों एवं जवानों ने भाग लेकर धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा।इस मौके पर कोबरा बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी अखिलेश, द्वितीय कमान अधिकारी अजीत, डिप्टी कमांडेंट नरेंद्र सहित अन्य मौजूद थे।

स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हजारीलाल के नाम पर सड़क का नामकरण, कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने किया लोकार्पण

आजादी के महानायकों का त्याग और बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा उनका संघर्ष : डॉ. अरविंद शर्मा

स्वतंत्रता सेनानियों की गौरवशाली विरासत को सहेजना और उनके सपनों का भारत बनाना हम सभी का दायित्व : डॉ. अरविंद शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और विरासत के संरक्षण को मिल रही प्राथमिकता







परिवहन विशेष न्यूज

बहादुरगढ़, 20 अक्टूबर। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने मंगलवार को बहादुरगढ़ के गांव टांडा हेड़ी में महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हजारीलाल के नाम पर सड़क का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, तपस्या और बलिदान भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। आज हम जिस स्वतंत्र और सशक्त भारत में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष और बलिदान से रखी थी। ऐसे महान सपूतों का सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है, उन्होंने गांव स्थित मंदिर में भी पूजा अर्चना की।

कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हजारीलाल को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाम पर सड़क का नामकरण करना उनके संघर्ष, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अब इस सड़क से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हजारीलाल के योगदान को याद करेगा। विशेष रूप से युवा पीढ़ी को यह जानने और समझने का अवसर मिलेगा कि देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्ष किए और कितनी कुर्बानियां दीं।

स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना जरूरी : डॉ. अरविंद शर्मा

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान केवल समारोह आयोजित करने या स्मारक बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों, विचारों और राष्ट्रसेवा की भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना जरूरी है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। उनका जीवन हमें एकता, भाईचारे, देशप्रेम और समाजसेवा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में महापुरुषों की विरासत को मिल रहा सम्मान

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपने स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में हमें उन सभी ज्ञात-अज्ञात सेनानियों को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता, जनभावनाओं का रखा जाएगा सम्मान

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों की पहचान केवल उनके विकास कार्यों से नहीं, बल्कि उनके गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और महान विभूतियों से भी होती है। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हजारीलाल के नाम पर सड़क का नामकरण इसी गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षित रखना है। स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को जीवित रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास और महान पूर्वजों के योगदान से परिचित हो सकें।

आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हजारीलाल के योगदान को याद किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने ग्रामीणों से स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को आत्मसात करने और समाज में एकता, भाईचारे तथा राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कपूर सिंह दलाल, आजाद दलाल, रणधीर दलाल, धर्मपाल वशिष्ठ, संतराम शर्मा, भगत लाल सरपंच, कृष्णा नंबरदार, पंकज जैन, भीम सिंह प्रणामी, विनोद जून, कृष्ण भारद्वाज, देवेंद्र जून आदि उपस्थित रहे।

पराली प्रबंधन स्कीम का लाभ उठाएं किसान : डीसी



फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर प्रशासन सख्त, क्विक रेस्पॉन्स टीमें सक्रिय

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 20 अक्टूबर

जिलाभर में पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ ही पराली जलाने व प्रदूषण फैलाने वाले घटकों पर प्रभावी रोक लगाने और वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुए फील्ड में नियमित निगरानी की जाए।

उन्होंने संभावित पराली जलाने की घटनाओं की तत्काल सूचना और प्रभावी कार्रवाई के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम सक्रिय रखने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। इसलिए किसानों को निरंतर जागरूक करते हुए पराली न जलाने और फसल अवशेष प्रबंधन की वैज्ञानिक एवं वैकल्पिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

फील्ड विजिट के साथ संभावित क्षेत्रों पर रखें पैनी नजर

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने और पराली जलाने की आशंका वाले क्षेत्रों में पहले से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाले संभावित स्रोतों की निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार ड्रोन का उपयोग करने तथा संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। उन्होंने भुवन एप और सीआरएम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।

पराली प्रबंधन अपनाने पर किसानों को प्रति एकड़ मिलेगी 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि

डीसी ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली को खेत में मिलाने पर किसानों को प्रति एकड़ 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना सहित फसल अवशेष प्रबंधन की उपलब्ध तकनीकों की जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने पंचायतों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अभियान से जोड़ने तथा किसानों के साथ निरंतर संवाद करने के निर्देश दिए। किसानों को पराली प्रबंधन से होने वाले पर्यावरणीय और कृषि संबंधी लाभों के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति निभाए सक्रिय भागीदारी

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए पराली जलाने की समस्या का प्रभावी समाधान जरूरी है। जिला प्रशासन इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करते हुए फसल अवशेष न जलाएं और उपलब्ध फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

डीसी आज बहादुरगढ में सुनेंगी नागरिकों की समस्याएं

सुबह 11 बजे लघु सचिवालय स्थित कैंप कार्यालय में होगी जनसुनवाई, सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद

बहादुरगढ़, 20 अक्टूबर। *बहादुरगढ क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार, 21 अक्टूबर को लघु सचिवालय बहादुरगढ स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई होगी। डीसी वर्षा खांगवाल बुधवार सुबह 11 बजे नागरिकों की समस्याएं सुनेंगी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगी। जनसुनवाई के दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, ताकि नागरिकों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जा सके। नागरिकों से अपील है की कि वे निर्धारित समय पर पहुंचकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखते हुए समाधान करवाएं।*

एकमुश्त कर निपटान योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा- हरियाणा सरकार की एकमुश्त निपटान योजना व्यापारियों के लिए लाभकारी

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर,20 अक्टूबर

हरियाणा सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को लाभ देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान स्कीम को व्यापारियों ने प्राथमिकता देते हुए उसका भरपूर लाभ उठाया है। इस स्कीम की अभूतपूर्व कामयाबी को देखते हुए सरकार द्वारा एक बार फिर निपटान योजना की तिथि को बढ़ाकर अब 30 नवम्बर कर दिया है। व्यापारी वर्ग अब 30 नवम्बर 2026 तक इस योजना का लाभ उठाकर पुराने बकाया करों का भुगतान सकते हैं। यह जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल ने दी।

डीसी ने बताया कि इससे जीएसटी में कम से कम बकाया राशियों के साथ आगे बढ़ा जाए ताकि जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में अधिक से अधिक समय और ध्यान दिया जा सके।

डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा गत 1 जून से एक मुश्त निपटान स्कीम, 2026 शुरू की है। जिसके तहत सात कराधान अधिनियमों के तहत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का प्रावधान है। यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में 1 लाख रुपये तक का कर बकाया है तो उसे इस स्कीम में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका उस वर्ष के लिए उस अधिनियम में संपूर्ण कर, ब्याज एवं जुर्माना राशि माफ हो जाएगी। आवेदक अपने बकाया देय राशि के निपटान के लिए किसी भी अधिनियम में किसी भी वर्ष के लिए आवेदन कर सकता है। पूर्ववर्ती हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए विशेष छूट उपलब्ध है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को 1 अप्रैल, 2003 से हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के लागू होने के साथ निरस्त कर दिया गया था। हरियाणा सामान्य बिक्री कर के तहत बकाया देय बहुत पुराने हैं, इसलिए 1 लाख से अधिक कर बकाया वाले सभी मामलों में 70 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

वैधानिक प्रपत्रों के जमा न करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि का होगा भुगतान

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल्स अजय कुमार ने बताया कि फार्म सी, फार्म एफ, फार्म एच, फार्म ई1, फार्म ई2, टैक्स इनवॉइस/वैट सी-4, वैट डी1, वैट डी2 आदि जैसे वैधानिक प्रपत्रों के न जमा करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि देय है। इन बकाया को विशेष रूप से लक्षित करने के लिए एक नई छूट प्रस्तावित की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अब ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है, तो उसके कर की मांग उन प्रपत्रों के प्रस्तुत करने से प्राप्त होने वाली छूट की राशि से घटा कर कम कर दी जाएगी, बशर्ते ये प्रपत्र तीन महीने के भीतर सत्यापित हो जाएं। यह लाभ ऐसे फर्जी/नकली फर्मों को उपलब्ध नहीं होगा जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। यह लाभ उन वैधानिक प्रपत्रों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें पहले प्राधिकरणों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह केवल हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से संबंधित बकाया राशि पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत प्रदान की गई कर छूट में एक रुपए से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, अन्य मामले में कर छूट का 70 प्रतिशत है। अन्य अधिनियमों के अधीन उपलब्ध छूट में एक रुपये से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, 1 लाख से 10 लाख तक 60 प्रतिशत, 10 लाख से 1 करोड़ तक 50 प्रतिशत, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 40 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ तक 35 प्रतिशत, 30 करोड़ रुपये से 60 करोड़ तक 30 प्रतिशत, 60 करोड़ रुपये से अधिक पर 0 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ब्याज तथा जुर्माना राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई है।



बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ

डीईटीसी ने बताया कि आवेदक को प्रत्येक पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ उसके बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा। बकाया राशि निर्धारित करने वाले किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील या मुकदमे में शामिल आवेदक भी लंबित अपीय या मुकदमे को वापस लेने की शर्त के साथ इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते है। निपटान की राशि का भुगतान किस्तों में करने की भी सुविधा स्कीम में दी जा रही है। पांच लाख रुपए तक के निपटान की राशि के लिए कोई किस्त नहीं। पांच लाख रुपए से अधिक और पच्चीस लाख रुपए तक के निपटान की राशि के लिए दो समान किस्तें। एक किस्त आवेदन जमा करते समय और दूसरी अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर। पच्चीस लाख रुपए से अधिक के निपटान की राशि के लिए तीन किस्तें होगी। आवेदन जमा करते समय निपटान राशि का 40 प्रतिशत, अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर दूसरी किस्त, निपटान राशि का 30 प्रतिशत और अंतरिम आदेश की तिथि से 120 दिनों के भीतर शेष राशि की तीसरी किस्त। ऐसे मामलों में जहां निपटान के लिए आवेदन सही पाया गया है और स्वीकार कर लिया गया है तो आवेदक के खिलाफ कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।

लुवास में कश्मीर के 20 पशुपालकों का पाँच दिवसीय अंतरराज्यीय डेयरी प्रशिक्षण संपन्न

वैज्ञानिक डेयरी फार्मिंग, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन पर दिया गया विशेष जोर

हरियाणा हिसार// राजेश सलूजा

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), हिसार के विस्तार शिक्षा निदेशालय द्वारा "सतत, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभकारी डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा" विषय पर आयोजित पाँच दिवसीय अंतरराज्यीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। कुलपति प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार वर्मा के दिशा-निर्देशन तथा निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. गौतम के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कश्मीर से आए 20 पशुपालकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन तकनीकों से अवगत कराकर दुग्ध उत्पादन, गुणवत्ता और आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना था।

समापन समारोह में पैरा पशुचिकित्सा विज्ञान संस्थान, लुवास, हिसार के निदेशक डॉ. संजय यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियाँ अपनाने तथा आधुनिक डेयरी प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि इन उपायों से उत्पादन लागत को नियंत्रित करने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को उन्नत नस्लों का चयन, वैज्ञानिक आवास एवं प्रजनन प्रबंधन, संतुलित पशु आहार, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दूध प्रसंस्करण, चारा संरक्षण एवं साइलेज निर्माण, पशुजन्य रोगों की रोकथाम, जैव सुरक्षा तथा पशु अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों ने हरियाणा के पशुपालकों के डेयरी फार्मों का भ्रमण कर आधुनिक तकनीकों एवं बेहतर प्रबंधन प्रणालियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।

इस अवसर पर डॉ. गौतम, निदेशक विस्तार शिक्षा, लुवास ने कहा कि विस्तार शिक्षा निदेशालय का प्रमुख उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवीन तकनीकों को किसानों और पशुपालकों तक पहुँचाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान पशुपालकों के डेयरी व्यवसाय को अधिक टिकाऊ एवं लाभकारी बनाने में सहायक होगा। उन्होंने विभिन्न राज्यों के पशुपालकों के बीच ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान को भी महत्वपूर्ण बताया।

कश्मीर के पशुपालन विभाग की विस्तार एवं प्रचार शाखा के विस्तार अधिकारी श्री मंजूर अहमद वानी के मार्गदर्शन में आए प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी की। समापन समारोह के दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए तथा अतिथियों द्वारा उन्हें प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय विस्तार विशेषज्ञ डॉ. सरिता ने किया। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, विषय विशेषज्ञों, निदेशालय विस्तार शिक्षा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा और कश्मीर के पशुपालकों के बीच वैज्ञानिक जानकारी एवं व्यावहारिक अनुभवों के आदान-प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा। इससे प्रतिभागियों को आधुनिक डेयरी तकनीकों को अपनाने, उत्पादन लागत कम करने, दुग्ध गुणवत्ता सुधारने तथा डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाने के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई।



अवैध पार्किंग पर पुलिस की सख्ती, लेकिन सवाल- जब जगह ही नहीं तो वाहन कहां खड़े करें?

राउरकेला में टोइंग की चेतावनी से वाहन चालकों में चिंता; यातायात अनुशासन जरूरी, पर पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला।

शहर की सड़कों को जाममुक्त रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से राउरकेला पुलिस ने निर्धारित पार्किंग स्थलों के बाहर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि नियमों के उल्लंघन पर वाहनों को टो करके हटाया जा सकता है। यातायात अनुशासन की दृष्टि से यह कदम महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ एक बुनियादी सवाल भी उठता है—जब शहर में पर्याप्त और सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो, तब आम नागरिक अपने वाहन आखिर कहां खड़े करें?

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करें और सड़क किनारे अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहन खड़ा करने से बचें। बेतरतीब पार्किंग से सड़क की उपलब्ध चौड़ाई घटती है, यातायात बाधित होता है और पैदल चलने वालों सहित अन्य राहगीरों को परेशानी होती है। इस समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता।

नियमों के साथ सुविधाओं की जवाबदेही भी जरूरी हालांकि, शहर में बढ़ती वाहनों की संख्या के अनुरूप पार्किंग स्थलों की उपलब्धता और उनकी उपयोगिता पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यस्त मार्गों पर आने वाले लोगों के लिए यदि पर्याप्त, सुलभ और व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो केवल कार्रवाई की चेतावनी समस्या का स्थायी समाधान नहीं बन



सकती।

ऐसी स्थिति में नागरिकों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी होती है—एक ओर वाहन खड़ा करने की जगह तलाशना और दूसरी ओर टोइंग की कार्रवाई का भय। इससे अनावश्यक परेशानी और असमंजस पैदा हो सकता है।

कार्रवाई के साथ समाधान भी दे

प्रशासन यातायात नियमों का पालन नागरिकों का दायित्व है, लेकिन पार्किंग की समुचित व्यवस्था करना भी संबंधित प्रशासन और नगर निकाय की जिम्मेदारी है। जरूरत इस बात की है कि पर्याप्त पार्किंग स्थल चिह्नित किए जाएं, स्पष्ट संकेतक लगाए जाएं और नागरिकों को वैकल्पिक स्थानों की जानकारी दी जाए।

राउरकेला को जाममुक्त बनाने की मुहिम तभी प्रभावी होगी, जब सख्ती के साथ सुविधाओं का विस्तार भी हो। सवाल नियमों का विरोध करने का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि व्यवस्था ऐसी हो जिसमें अनुशासन भी कायम रहे और आम नागरिक अनावश्यक परेशानी से भी बचे।

रावण के साथ भ्रष्टाचार, शोषण और मिलावटखोरी का पुतला दहन

BS-IV वाहनों पर प्रतिबंध और महंगे चालानों के खिलाफ परिवहन जगत ने जताया विरोध: संजय सम्राट

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर 2026। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट के नेतृत्व में दशहरे के अवसर पर रावण के साथ भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण और मिलावटखोरी के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया। इस दौरान दवाइयों, दूध, घी, तेल और खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ E20 पेट्रोल को लेकर वाहन अनुकूलता संबंधी चिंताओं तथा प्रदूषण के नाम पर BS-IV डीजल टैक्सी-बसों पर प्रतिबंध, पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने की नीति और महंगे ट्रैफिक चालानों के खिलाफ आवाज उठाई गई। संजय सम्राट ने कहा कि इन समस्याओं से टैक्सी-बस संचालकों और ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हो रही है।



वहीं, खाद्य पदार्थों में मिलावट आम जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने मांग की कि ईंधन की गुणवत्ता और वाहन अनुकूलता की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा परिवहन व्यवसायियों को राहत देने के लिए व्यावहारिक नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा, "रावण दहन का वास्तविक उद्देश्य समाज से बुराइयों का अंत करना है। हमारा संकल्प है कि देश से भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, अन्याय और शोषण समाप्त हो, भारत समृद्ध बने तथा देशवासी स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहें।"

संजय सम्राट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से परिवहन जगत की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने तथा वाहन प्रतिबंधों और महंगे चालानों की समीक्षा कर छोटे परिवहन व्यवसायियों एवं ड्राइवरों के हितों की रक्षा करने की मांग की।

देवी दुर्गा विसर्जन और विजयादशमी पर रावण दहन

मुरहू -खूंटी में आस्था का संगम

डॉ दीपक कुमार घोष

खूंटी।विजयादशमी के पावन पर्व पर पूरे खूंटी जिले के साथ-साथ मुरहू प्रखंड में भी माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ शारदीय नवरात्र का समापन भावुक माहौल में हो गया। विजयादशमी का पर्व भी हर्षोल्लास से मनाया गया। मुरहू के महादेव मंडा, तोरपा, कुंजला, रनिया, कोड़ाकेल,गनालोया आदि जगहों में नवरात्र के तीसरे दिन से ही सभी समाजों के लोग एकजुट होकर माँ चंद्रघंटा सहित दुर्गा पूजा में शामिल हो रहे हैं, जो सामाजिक एकता का संदेश दे रहा है।खूंटी के प्रसिद्ध हरि मंदिर में वर्षों से चली आ रही दुर्गा पूजा परंपरा भक्तिमय और मनोरम होता है। यहाँ विजयादशमी पर सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य विशेष आकर्षण रहता है और दशमी को प्रतिमा विसर्जन के साथ उत्सव का समापन होता है।मुरहू में श्रद्धालु माँ की प्रतिमा को बस्ती -गांव भ्रमण कराते हुए नदी और सरोवर तट तक ले जाते हैं। कम पानी वाले सरोवर किनारे, जहाँ दूसरी तरफ घास-फूस और कांस के पौधे हैं, वहीं पर सामूहिक रूप से पीठ दिखाकर विनम्र भाव से माँ को विदा किया जा रहा है। तैरते दीये, फूल और ₹अगले बरस तू जल्दी आइ के जयकारों के साथ वातावरण भावुक बना हुआ है। खूंटी कोड़ाकेल, तोरपा आदि जगहों पर रावण दहन का भी कार्यक्रम हुआ।

स्थानीय लोगों का मानना है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देकर अपने धाम लौटती हैं, इसलिए विसर्जन सिर्फ परंपरा नहीं, आस्था का पर्व है।



राउरकेला की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर संकट: स्थायी ठेका नहीं, अस्थायी इंतजाम से कब तक चलेगा शहर?



निव एनर्जी के अनुबंध नवीनीकरण पर सवाल, कथित तौर पर एक-दो महीने के विस्तार से चल रहा काम; अंधेरी सड़कों और खराब उपकरणों की समस्या पर नगर निगम की जवाबदेही चर्चा में

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

शहर की सड़कों को रोशन रखने वाली व्यवस्था यदि खुद अनिश्चितता के अंधेरे में हो, तो इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। राउरकेला महानगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों, बिजली के खंभों और संबंधित उपकरणों के रखरखाव को लेकर ऐसी ही स्थिति सामने आने के दावे किए जा रहे हैं। आरोप है कि निव एनर्जी से संबंधित अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है और व्यवस्था को एक-दो महीने के अस्थायी विस्तार के सहारे चलाया जा रहा है।

स्थायी व्यवस्था के अभाव में शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रकाश व्यवस्था प्रभावित होने तथा शिकायतों के समाधान में कठिनाई आने की बात कही जा रही है। नगर निगम से संपर्क करने पर भी स्पष्ट और दीर्घकालिक समाधान नहीं मिलने का दावा है। हालांकि, संबंधित कंपनी के अनुबंध, नवीनीकरण की स्थिति और निगम के आधिकारिक जवाब की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

निविदाएं जारी, लेकिन रखरखाव की व्यापक व्यवस्था पर सवाल ओडिशा सरकार के ई-निविदा पोर्टल पर वर्ष 2026 में राउरकेला में स्ट्रीट लाइटों के विस्तार, मरम्मत और स्थापना से संबंधित कई निविदाएं दर्ज हैं। इनमें जनता निवास गली, वार्ड-30 में लाइटों के विस्तार तथा फिटिंग से संबंधित निविदा भी शामिल है।

वहीं, नौ अक्टूबर 2026 को अंबेडकर चौक से पानपोष गांधी चौक मार्ग पर स्ट्रीट लाइट फिटिंग और ओवरहेड केबल लगाने के लिए लगभग 46.91 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली निविदा प्रकाशित हुई। ये निविदाएं प्रकाश व्यवस्था के लिए अलग-अलग कार्यों की प्रक्रिया दर्शाती हैं, लेकिन इनसे निव एनर्जी के मुख्य अनुबंध या उसके नवीनीकरण की स्थिति की पुष्टि नहीं होती।

जवाबदेही तय हो, नागरिकों को मिले राहत सवाल यह है कि यदि रखरखाव की व्यवस्था अस्थायी विस्तार पर निर्भर है, तो स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा? नगर निगम को अनुबंध की स्थिति, वैकल्पिक व्यवस्था, शिकायत निवारण और खराब लाइटों की मरम्मत की समयसीमा सार्वजनिक करनी चाहिए।

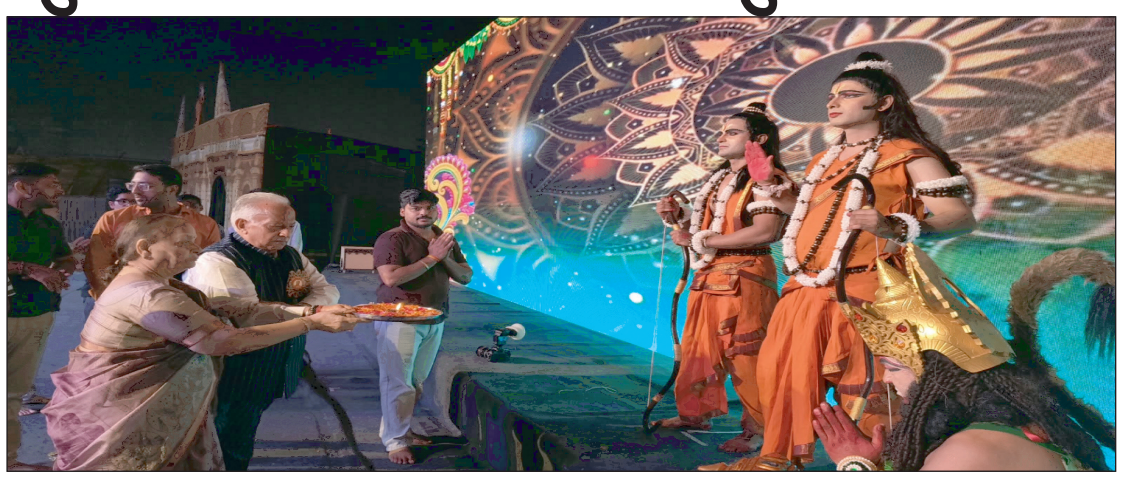
शहर की प्रकाश व्यवस्था केवल सुविधा नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और नागरिकों की आवाजाही से जुड़ा बुनियादी दायित्व है। अस्थायी इंतजाम यदि लंबे समय तक चलते हैं, तो उनकी समीक्षा और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। अब निगाहें राउरकेला महानगर निगम के स्पष्ट आधिकारिक पक्ष और स्थायी समाधान की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर हैं।



नव श्री केशव रामलीला कमेटी रोहिणी : नव श्री केशव रामलीला में हुआ 200 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन

रामलीला में आज रावण वध व राजतिलक संवाद ने लोगों का मनमोहा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क, सेक्टर 11 के सामने भगवान गणेश के आह्वान के साथ नव श्री केशव रामलीला में आज रावण वध व राजतिलक संवाद ने लोगों का मनमोहा। नव श्री केशव रामलीला कमेटी के चेयरमैन पुष्पेन्द्र रस्तोगी ने कहा जापानी पार्क में 200 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया, जो 200 फीट ऊंचा रावण मजबूती से खड़ा हुआ था वह लोगों के बीच में आकर्षण का केन्द्र बना था। यह रोहिणी में सबसे ऊंचे पुतलों में से एक था। रावण का चेहरा 25 फीट ऊंचा है और रिमोट से इसका दहन किया गया था।



रामलीला में रावण वध व राजतिलक के संवाद ने दर्शकों को भावुक किया। रावण वध व राम के राजलितक से संबंधित संवादों ने लोगों का मनमोह लिया, खासकर राम की विजय व उनके राजतिलक का उत्सव देखकर लोग आनंदित हुए। यह प्रसंग रामायण की कथा से जुड़ा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत व धर्म की स्थापना को दर्शाता है, जिसके कारण दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।

उन्होंने बताया कि इस बार त्रिदेव थीम पर इस बार तीन मंजिला भव्य स्टेज पर लीला का मंचन हो रहा था। इस अवसर पर संस्था चेयरमैन पुष्पेन्द्र रस्तोगी, अध्यक्ष जय किशन बंसल, एडिशनल चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, महामंत्री कृष्ण जिंदल, लीला मंत्री हरि किशन मित्तल, कोषाध्यक्ष दिनेश सर्राफ, कार्यालय महामंत्री पुरुषोतम लाल सिंघल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

इतिहास की परतों में छुपी स्त्री, संस्कृति और सभ्यता का पुनर्पाठ: राखीगढ़ी में भारतीय स्त्री की ऐतिहासिक भूमिका की तलाश

हड़प्पा की सबसे बड़ी बस्ती से मिले साक्ष्य – स्त्री को प्रतीक नहीं, स्वतंत्र ऐतिहासिक विषय मानने की जरूरत

प्रस्तुतकर्ता पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता परिवहन विशेष समाचार पत्र

तथ्य एक नजर में

- स्थान: राखीगढ़ी, हिसार जिला, हरियाणा — हड़प्पा / सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल
- साक्ष्य: नियोजित बस्ती, जल-निकासी, पकी ईंटें, मुहरें, मनके, मृद्भांड, शिल्प-सामग्री, कब्रिस्तान, मानव अवशेष
- काल: प्रारंभिक हड़प्पा से विकसित हड़प्पा तक के चरण — हरियाणा पुरातत्व विभाग के अनुसार
- आनुवंशिक अध्ययन: 2019 में Cell में प्रकाशित शोध — एक महिला के अवशेषों से प्राप्त डीएनए, प्राचीन ईरानी कृषक और दक्षिण एशियाई शिकारी-संग्राहक वंश से संबंध, स्टेपी घटक अनुपस्थित

मुख्य बिंदु

- इतिहास केवल राजाओं-युद्धों का वृत्तांत नहीं, स्त्री के श्रम, विश्वास और सांस्कृतिक योगदान की कहानी भी है
- शंख की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण, अर्ध-मूल्यवान पत्थरों से स्त्री की भौतिक संस्कृति में उपस्थिति स्पष्ट, पर उनसे सामाजिक प्रतिष्ठा का सीधा निष्कर्ष उचित नहीं
- 'डांसिंग गर्ल' मोहनजोदड़ो की है, राखीगढ़ी की नहीं — प्रतिमा की व्याख्या के लिए संदर्भ जरूरी है
- एक महिला के डीएनए से पूरी सभ्यता, भाषा या आर्य प्रवासन का अंतिम उत्तर नहीं निकलता
- लोकश्रुति और प्रमाण में अंतर रखना जरूरी — राखीगढ़ी के नाम से जुड़ी महाभारत कथा जनश्रुति है, स्थापित तथ्य नहीं

1. राखीगढ़ी: मिट्टी में सुरक्षित स्मृति

राखीगढ़ी की पहचान आधुनिक उत्खननों से व्यापक हुई है। नियोजित आवास, गलियाँ, जल-निकासी, मानकीकृत बाट-माप, शिल्प-उत्पादन की वस्तुएँ — ये सब संगठित समाज की गवाही देते हैं। कब्रिस्तान विशेष महत्त्व



रखता है, क्योंकि वह उन लोगों के जीवन-मृत्यु संस्कारों पर प्रश्न उठाता है, जिनकी व्यक्तिगत आवाजें इतिहास में सुरक्षित नहीं रहीं। कब्रों में मृद्भांड, आभूषण और अन्य वस्तुएँ मान्यताओं और सामाजिक प्रथाओं को समझने में मदद करती हैं, पर किसी एक वस्तु से पूरे समाज की संरचना का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

2. शंख की चूड़ियाँ और स्त्री की उपस्थिति महिला कंकालों के साथ शंख की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण मिले हैं। चूड़ियाँ केवल सजावट थीं या वैवाहिक स्थिति, सामाजिक पहचान, धार्मिक विश्वास से जुड़ी थीं — यह शोध की माँग करता है। आज के अर्थों को हजारों साल पुराने समाज पर बिना प्रमाण लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी यह स्पष्ट है: प्राचीन स्त्री केवल राजा की पत्नी या योद्धा की माता नहीं थी, वह समुदाय की सदस्य थी, जिसके श्रम और सांस्कृतिक व्यवहारों ने सभ्यता को आकार दिया।

3. स्त्री, शिल्प और सांस्कृतिक जीवन मनके, धातु-कर्म, मृद्भांड, मुहरें, आभूषण — हड़प्पा की विकसित कला-चेतना दिखाते हैं। स्त्रियों की भागीदारी कितनी थी, उनके श्रम का आर्थिक महत्त्व क्या था — इसके लिए पुरातत्व, मानवशास्त्र और तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है।

4. आनुवंशिक अध्ययन — विज्ञान और व्याख्या में अंतर 2019 के शोध से पता चला कि विकसित हड़प्पा काल में उत्तर-पश्चिमी दक्षिण एशिया की आबादी में स्टेपी घटक अनिवार्य नहीं था। यह महत्त्वपूर्ण है, पर यह आर्य आक्रमण/प्रवासन की सभी बहसों का निर्णायक उत्तर नहीं है। आनुवंशिकी, पुरातत्व, भाषाविज्ञान और साहित्यिक स्रोत अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं।

5. हड़प्पा और वैदिक परंपरा राखीगढ़ी में अग्निवेदियों/अग्निकुंडों जैसी संरचनाओं का उल्लेख मिलता है। पर आकार या अग्नि से संबंध मात्र वैदिक यज्ञ की पुष्टि नहीं करता। निरंतरता और परिवर्तन — दोनों संभावनाओं को खुला रखना होगा।

6. संरक्षण और शैक्षिक दायित्व राखीगढ़ी को केवल पर्यटन आकर्षण न बनाया जाए। वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटल अभिलेखन, शोध-सुविधा, प्रमाण-आधारित जानकारी और स्थानीय समुदाय — विशेषकर महिलाओं, युवाओं, शिक्षकों की भागीदारी जरूरी है। पाठ्यक्रमों में प्रमाण विश्लेषण सिखाया जाए, स्त्री के अनुभव, श्रम और योगदान को स्थान मिले।

संपादकीय टिप्पणी

राखीगढ़ी का वास्तविक महत्त्व किसी पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष को सिद्ध करने में नहीं, बल्कि नए प्रश्न उठाने में है। जब स्त्री को इतिहास में केवल प्रतीक नहीं, स्वतंत्र विषय माना जाएगा, तभी सभ्यता की तस्वीर संपूर्ण होगी।

पारंपरिक परीक्षाओं से आगे: प्रश्नपत्र लीक-मुक्त परीक्षा प्रणाली का निर्माण





● डॉ. विजय गर्ग

पारंपरिक परीक्षा प्रणाली कई चरणों और व्यक्तियों की लंबी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। प्रश्नपत्र तैयार करने, उनकी समीक्षा करने, छपाई, पैकिंग, परिवहन, सुरक्षित भंडारण और परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण पर सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा रहता है। एक छोटी-सी चूक भी पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को परीक्षा रद्द करनी पड़ सकती है, दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ सकती है और अनियमितताओं की जाँच करनी पड़ती है।

शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करती हैं, उनकी समझ को परखती हैं तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और भविष्य में रोजगार के अवसरों का मार्ग निर्धारित करने में सहायता करती हैं। लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ वर्षों की मेहनत, त्याग और आशाओं का प्रतीक होती हैं। लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने, नकल और अन्य अनियमितताओं की घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। तेजी से विकसित हो रही तकनीक के इस युग में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: क्या आधुनिक तकनीक की सहायता से एक सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं से मुक्त परीक्षा प्रणाली बनाई जा सकती है?

चुनौती केवल प्रश्नपत्रों को लीक होने से रोकने की नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने और प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता का निष्पक्ष अवसर प्रदान करने की भी है।

परीक्षा सुरक्षा की बढ़ती चुनौती

पारंपरिक परीक्षा प्रणाली कई चरणों और व्यक्तियों की लंबी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। प्रश्नपत्र तैयार करने, उनकी समीक्षा करने, छपाई, पैकिंग, परिवहन, सुरक्षित भंडारण और परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण पर सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा रहता है। एक छोटी-सी चूक भी पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को परीक्षा रद्द करनी पड़ सकती है, दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ सकती है और अनियमितताओं की जाँच करनी पड़ती है।

इसके परिणाम केवल प्रशासनिक कठिनाइयों तक सीमित नहीं रहते। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव, निराशा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। परिवारों को यात्रा, आवास और कोचिंग पर किए गए खर्च का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ईमानदारी से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी मेहनत व्यर्थ चली गई। दूसरी ओर, संस्थानों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। बार-बार होने वाली अनियमितताएँ युवाओं के मन में शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता के प्रति विश्वास को कमजोर कर सकती हैं।

तकनीक के विकास के साथ परीक्षा में धांधली करने के तरीके भी अधिक जटिल होते जा रहे हैं। प्रश्नपत्रों की तस्वीरें मैसेजिंग ऐप के माध्यम से तेजी से फैल सकती हैं, चोरी की गई डिजिटल फाइलें साझा की जा सकती हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग पहचान संबंधी धोखाधड़ी के कुछ तरीकों में किया जा सकता है। इसलिए परीक्षा सुरक्षा को उभरते खतरों के अनुरूप विकसित करना आवश्यक है।

डिजिटल तकनीक: सुधार का एक नया अवसर

यदि तकनीक का उपयोग सावधानी और उचित योजना के साथ किया जाए, तो यह परीक्षा सुरक्षा को मजबूत बनाने के कई अवसर प्रदान करती है।

1. एनक्रिप्ट किए गए डिजिटल प्रश्नपत्र

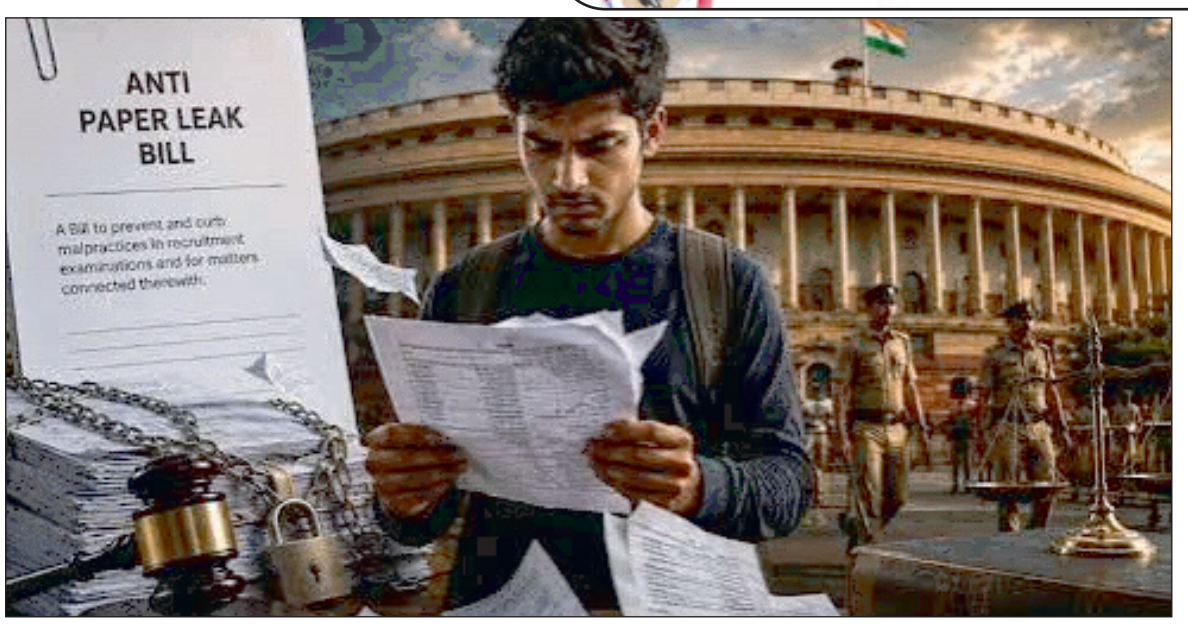
छपे हुए प्रश्नपत्रों के भौतिक परिवहन पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय परीक्षा संस्थाएँ एनक्रिप्ट की गई डिजिटल फाइलों का उपयोग कर सकती हैं। ऐसी फाइलों को अधिकृत डिक्रिप्शन कुंजियों के बिना पढ़ना कठिन होता है। इन्हें सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा सकता है और परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही खोला जा सकता है।

इस प्रक्रिया में कई स्तरों पर अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। प्रत्येक पहुँच और कार्रवाई का ऐसा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, जिसमें बाद में किए गए अनधिकृत बदलावों का पता लगाया जा सके। फिर भी, केवल एनक्रिप्शन पर्याप्त नहीं है। यदि अधिकृत व्यक्ति अपनी पहुँच का दुरुपयोग करें या कंप्यूटर प्रणाली से समझौता हो जाए, तो सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण भी आवश्यक हैं।

2. कंप्यूटर आधारित परीक्षाएँ

कंप्यूटर आधारित परीक्षाएँ बड़ी संख्या में प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण से जुड़े कुछ जोखिमों को कम कर सकती हैं। सुरक्षित प्रश्न बैंक से प्रश्न चुनकर अलग-अलग विद्यार्थियों को अलग, लेकिन कठिनाई के स्तर में समान प्रश्नपत्र दिए जा सकते हैं।

प्रश्नों का यादृच्छिक चयन संगठित नकल को कठिन बना सकता है। स्वचालित मूल्यांकन से मानवीय त्रुटियों की कुछ संभावनाएँ भी कम हो सकती हैं। हालाँकि, कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए विश्वसनीय तकनीकी ढाँचा, सुरक्षित सॉफ्टवेयर, बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था और तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए उचित प्रबंध आवश्यक हैं।



3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता परीक्षा में धोखाधड़ी के संकेत देने वाले असामान्य पैटर्न की पहचान करने में सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए, उत्तरों में संदिग्ध समानता, लॉगिन करने के असामान्य तरीके या परीक्षा केंद्रों के रिकॉर्ड में अनियमितताओं का पता डेटा विश्लेषण के माध्यम से लगाया जा सकता है।

लेकिन ऐसे संकेतों को दोष सिद्ध करने का आधार नहीं, बल्कि आगे की जाँच की आवश्यकता दर्शाने वाला साधन माना जाना चाहिए। निर्दोष विद्यार्थियों को गलत तरीके से दोषी ठहराने से बचाने के लिए मानवीय निगरानी, पारदर्शी प्रक्रियाएँ और अपील करने का अवसर आवश्यक हैं।

4. बायोमेट्रिक सत्यापन और सुरक्षित पहचान

चेहरे की पहचान, उँगलियों के निशान या पहचान सत्यापन की अन्य अधिकृत विधियाँ किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने की घटनाओं को कम करने में सहायक हो सकती हैं। ये उपाय जोखिम के अनुपात में होने चाहिए। जो उम्मीदवार किसी विशेष बायोमेट्रिक विधि का उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए वैकल्पिक पहचान प्रक्रिया भी उपलब्ध होनी चाहिए।

विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी को सख्त पहुँच नियंत्रण, डेटा को सीमित अवधि तक सुरक्षित रखने और लागू गोपनीयता कानूनों का पालन करके संरक्षित किया जाना चाहिए। तकनीक का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की रक्षा करना होना चाहिए, न कि विद्यार्थियों की निजता और गरिमा को अनावश्यक खतरे में डालना।

5. ब्लॉकचेन और छेड़छाड़-रोधी रिकॉर्ड

ब्लॉकचेन या अन्य छेड़छाड़-रोधी रिकॉर्ड प्रणालियों की सहायता से प्रश्नपत्रों तक पहुँच, अनुमोदन, हस्तांतरण और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का सत्यापन योग्य रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इससे अनधिकृत बदलावों का पता लगाना आसान हो सकता है।

हालाँकि, ब्लॉकचेन किसी अधिकृत व्यक्ति को प्रश्नपत्र निर्धारित समय से पहले लीक करने से अपने आप नहीं रोक सकता। इसका मुख्य लाभ जवाबदेही और प्रक्रियाओं की निगरानी बढ़ाने में है, न कि परीक्षा संबंधी धोखाधड़ी का संपूर्ण समाधान प्रदान करने में।

केवल तकनीक पर्याप्त नहीं है

एक सुरक्षित परीक्षा प्रणाली के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर ही पर्याप्त नहीं है। मानवीय व्यवहार, प्रशासनिक कमजोरियाँ और संस्थागत जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

सबसे पहले, परीक्षा संस्थाओं को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए कि प्रश्नपत्र तैयार करने, उनकी समीक्षा करने, उन तक पहुँच प्राप्त करने और अंतिम स्वीकृति देने की जिम्मेदारी किसकी होगी। किसी एक व्यक्ति के पास पूरी प्रक्रिया पर असीमित नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारियों का विभाजन और स्वतंत्र सत्यापन दुरुपयोग की संभावनाओं को कम कर सकते हैं।

दूसरा, कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जाँच, गोपनीयता समझौते, नियमित सुरक्षा ऑडिट और जानबूझकर की गई अनियमितताओं के लिए कठोर दंड एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होने चाहिए। गलत गतिविधियों की सूचना देने वालों को संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वे प्रतिशोध के डर के बिना संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दे सकें।

तीसरा, परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के समान मानक लागू किए जाने चाहिए। सुरक्षित भंडारण, सीमित पहुँच, जहाँ उचित हो वहाँ निगरानी कैमरे और प्रश्नपत्रों के हस्तांतरण का लिखित रिकॉर्ड सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। किसी अनियमितता का संदेह होने पर शीघ्र जाँच के लिए पहले से आपातकालीन योजनाएँ भी तैयार होनी चाहिए।

अंत में, अनियमितताएँ सामने आने पर परीक्षा संस्थाओं को पारदर्शी तरीके से जानकारी देनी चाहिए। सूचना देने में देरी, विरोधाभासी घोषणाएँ और अस्पष्ट निर्णय जनता के विश्वास को और कमजोर करते हैं। समय पर जानकारी, स्वतंत्र जाँच और जहाँ उचित हो वहाँ मुआवजे या अन्य राहत की व्यवस्था यह दर्शा सकती है कि विद्यार्थियों के हितों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

समानता और न्याय को प्राथमिकता

डिजिटल परीक्षाओं की ओर बढ़ते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि तकनीक तक पहुँच रखने वाले और इससे वंचित विद्यार्थियों के बीच नई खाई न पैदा हो। ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को अक्सर अस्थिर इंटरनेट, बिजली की कमी या कंप्यूटर चलाने के सीमित अनुभव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए सरकारों और परीक्षा संस्थाओं को पर्याप्त तकनीकी ढाँचे, सुलभ परीक्षा केंद्रों, अभ्यास परीक्षाओं और तकनीकी सहायता में निवेश करना चाहिए। वैकल्पिक बिजली व्यवस्था, जहाँ उपयुक्त हो वहाँ सुरक्षित ऑफलाइन सुविधाएँ और तकनीकी खराबी की स्थिति में अपनाए जाने वाले स्पष्ट नियम आवश्यक हैं।

तकनीक का उद्देश्य परीक्षाओं को अधिक निष्पक्ष बनाना होना चाहिए, न कि पहले से कठिनाइयों का सामना कर रहे विद्यार्थियों के लिए नई बाधाएँ पैदा करना।

परीक्षाओं के उद्देश्य पर पुनर्विचार

प्रश्नपत्र लीक होने से रोकना आवश्यक है, लेकिन व्यापक उद्देश्य मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार करना भी होना चाहिए। केवल एक अत्यधिक महत्वपूर्ण परीक्षा पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता विद्यार्थियों पर भारी मानसिक दबाव डालती है और अनुचित तरीकों को बढ़ावा दे सकती है।

एक संतुलित मूल्यांकन प्रणाली में परीक्षाओं के साथ विद्यालयी प्रदर्शन, प्रयोगात्मक कार्य, परियोजनाएँ और अन्य उपयुक्त मूल्यांकन विधियाँ शामिल की जा सकती हैं। ऐसी बहुआयामी प्रणाली भी पारदर्शी, जहाँ आवश्यक हो वहाँ मानकीकृत तथा पक्षपात और हेरफेर से सुरक्षित होनी चाहिए।

प्रश्न बैंकों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। परीक्षाओं में केवल रटकर उत्तर देने के बजाय अवधारणात्मक समझ, आलोचनात्मक चिंतन और समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन होना चाहिए। जब मूल्यांकन अधिक सार्थक और विविध होता है, तो शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमताओं को बेहतर ढंग से पहचान सकती है।

आगे की राह

प्रश्नपत्र लीक होने की संभावनाओं को न्यूनतम करने वाली परीक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए सरकारों, परीक्षा संस्थाओं, तकनीकी विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और समाज के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। सुरक्षा उपायों का स्वतंत्र परीक्षण होना चाहिए, उनकी नियमित समीक्षा की जानी चाहिए और उभरते खतरों के अनुसार उनमें सुधार किया जाना चाहिए। नई प्रणालियों को बड़े स्तर पर लागू करने से पहले छोटे स्तर पर उनका परीक्षण करने से तकनीकी कमजोरियों की पहचान की जा सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए। तकनीक संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर सकती है, जानकारी को सुरक्षित रख सकती है और विश्वसनीय रिकॉर्ड तैयार कर सकती है, लेकिन जवाबदेह संस्थाओं और नैतिक आचरण का कोई विकल्प नहीं है।

अंतिम उद्देश्य केवल प्रश्नपत्रों को लीक होने से रोकना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों की रक्षा करना, उनकी वास्तविक मेहनत को सम्मान देना और शिक्षा में विश्वास बनाए रखना है। शिक्षा को अवसरों तक पहुँचने का एक निष्पक्ष मार्ग बने रहना चाहिए।

एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली के लिए सुरक्षित तकनीक, जिम्मेदार प्रशासन और मजबूत नैतिक आधार का समन्वय आवश्यक है। भले ही प्रत्येक संभावित जोखिम को पूरी तरह समाप्त करना संभव न हो, लेकिन सुविचारित सुधारों, स्वतंत्र निगरानी और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता से ऐसी परीक्षा प्रणाली बनाई जा सकती है, जिसमें ईमानदारी सुरक्षित रहे, अनुचित गतिविधियाँ कठिन हों और प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता का निष्पक्ष अवसर मिले।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य। प्रख्यात वैज्ञानिक। शैक्षिक स्तंभकार
गली कौर चंद, एम.एच.आर.
मलोट, पंजाब – 152107

युद्ध और संघर्ष के बीच महिलाओं की अनकही कहानियाँ

डॉ. विजय गर्ग

युद्ध का वर्णन अक्सर सैन्य विजय, क्षेत्रों पर कब्जे, राजनीतिक वार्ताओं और रणनीतिक पराजयों के संदर्भ में किया जाता है। समाचारों में सेनाओं, हथियारों, तबाह हुए शहरों और शक्तिशाली नेताओं के बीच हुए समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेकिन इन सुर्खियों के पीछे एक दूसरी कहानी भी छिपी होती है, जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। यह उन महिलाओं की कहानी है, जो हिंसा और अनिश्चितता के बीच जीवित रहने, अपने परिवारों की रक्षा करने और अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में महिलाएँ केवल परिस्थितियों की असहाय शिकार नहीं होतीं, बल्कि वे जीवित बचने वाली, परिवारों की देखभाल करने वाली, शांति स्थापित करने वाली और युद्ध से तबाह हुए जीवन को फिर से सँवारने वाली साहसी व्यक्तित्व भी होती हैं।

संघर्ष की मानवीय कीमत

जब सशस्त्र संघर्ष शुरू होता है, तो महिलाओं को अक्सर एक साथ कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। बमबारी, विस्थापन, भोजन और दवाओं की कमी तथा आवश्यक सेवाओं का नष्ट होना उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। अस्पतालों तक पहुँचना कठिन हो जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं, आजीविका के साधन समाप्त हो जाते हैं और परिवार बिछड़ जाते हैं।

गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं और छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली माताओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा सहायता, सुरक्षित प्रसव की सुविधाएँ, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता सामग्री और साफ-सफाई की व्यवस्था सीमित हो जाती है। जब सड़कें बंद हों या स्वास्थ्य केंद्र नष्ट हो जाएँ, तो सामान्य चिकित्सा आवश्यकता भी जानलेवा आपातस्थिति बन सकती है।

संघर्ष का प्रभाव केवल शारीरिक चोटों तक सीमित नहीं रहता। हिंसा देखना, प्रियजनों को खोना और लगातार भय में जीना लंबे समय तक मानसिक पीड़ा का कारण बन सकता है। अनेक महिलाओं को अपने दुख और असुरक्षा के बावजूद बच्चों तथा बुजुर्गों की देखभाल जारी रखनी पड़ती है।

विस्थापन और घर खोने का दर्द

दुनियाभर में विस्थापित लाखों महिलाओं के लिए युद्ध का अर्थ केवल अपना घर खो देना नहीं है। इसके साथ रोजगार, शिक्षा, सामाजिक संबंध, निजी सामान और अपनी पहचान से जुड़े परिचित परिवेश का भी नुकसान होता है।

संघर्ष से बचकर निकलने वाली महिलाएँ अक्सर अपने बच्चों के साथ लंबी यात्राएँ करती हैं और उनके पास कुछ आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त बहुत कम सामान होता है। शरणार्थी शिविरों और अस्थायी आश्रय स्थलों में भीड़भाड़, स्वच्छता की कमी और निजता का अभाव उनके लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकता है। पहचान पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, आर्थिक सहायता और कानूनी संरक्षण तक पहुँचने में भी कठिनाई हो सकती है।

विस्थापन आर्थिक संकट को और गहरा कर देता है। जो महिलाएँ पहले परिवार के अन्य सदस्यों की आय पर निर्भर थीं, वे अचानक पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर हो सकती हैं। रोजगार, बच्चों की देखभाल की सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों के अभाव में स्वतंत्र जीवन दोबारा शुरू करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

लैंगिक हिंसा: एक छिपा हुआ संकट

सशस्त्र संघर्ष की सबसे चिंताजनक वास्तविकताओं में से एक लैंगिक हिंसा का बढ़ता खतरा है। यौन हिंसा, शोषण, जबरन विवाह, मानव तस्करी और घरेलू हिंसा की घटनाएँ तब बढ़ सकती हैं, जब कानूनी सुरक्षा कमजोर हो जाती है और सामाजिक व्यवस्था बिखर जाती है।

घर छोड़कर भागते समय, पानी लाने, भोजन तलाशने या सुरक्षित आश्रय तक पहुँचने के दौरान महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ परिस्थितियों में सशस्त्र समूह समुदायों को डराने, आबादी को दंडित करने या सामाजिक संबंधों को नष्ट करने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल करते हैं।

ऐसे अपराध शारीरिक चोटों, मानसिक आघात और दीर्घकालिक सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। कई पीड़ित महिलाएँ भय, सामाजिक कलंक, धमकियों या परिवार द्वारा अस्वीकार किए जाने की आशंका से चुप रहती हैं। उनकी चुप्पी को कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं समझना चाहिए कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ।

सरकारों, मानवीय सहायता संगठनों और स्थानीय समुदायों को सुरक्षित शिकायत व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। पीड़ितों को गोपनीय चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सहायता, प्रतिशोध से सुरक्षा और न्याय उपलब्ध कराना आवश्यक है। न्याय व्यवस्था संवेदनशील, सुलभ और पीड़ितों की आवश्यकताओं पर केंद्रित होनी चाहिए।

परिवार की देखभाल करने वाली और कमाने वाली महिलाएँ

संघर्ष के दौरान महिलाएँ अक्सर अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों से कहीं अधिक भूमिकाएँ निभाती हैं। जब पति या परिवार के अन्य सदस्य मारे जाते हैं, घायल होते हैं, कैद हो जाते हैं या परिवार से बिछड़ जाते हैं, तो महिलाओं को कमाने, निर्णय लेने और परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।



अनेक महिलाएँ सामुदायिक रसोई चलाती हैं, आवश्यक वस्तुएँ वितरित करती हैं, विस्थापित बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करती हैं तथा लापता परिजनों को खोजने में पड़ोसियों की सहायता करती हैं। कुछ महिलाएँ छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं, चिकित्सा केंद्रों में स्वयंसेवा करती हैं या राहत कार्यों में योगदान देती हैं।

इन प्रयासों को अक्सर उतना ध्यान नहीं मिलता, जितना सैन्य अभियानों और राजनीतिक वार्ताओं को मिलता है। फिर भी, साहस के ये छोटे-छोटे कार्य समुदायों को कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं।

महिलाओं की सहनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि उनसे हर प्रकार की पीड़ा सहने की अपेक्षा की जाए। उनके साहस का सम्मान करने के साथ-साथ उन्हें व्यावहारिक सहायता, समान अवसर और प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है।

शिक्षा, बच्चे और भविष्य

संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएँ अक्सर बच्चों के भविष्य की रक्षा करने की भावनात्मक जिम्मेदारी उठाती हैं। स्कूल बंद होने, विस्थापन और आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों की शिक्षा कई बार वर्षों तक बाधित रहती है। लड़कियों को कम उम्र में विवाह, शोषण, बिना वेतन के घरेलू काम और पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ देने जैसे खतरों का विशेष रूप से सामना करना पड़ सकता है।

शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि स्थिरता, आत्मविश्वास, सामाजिक जुड़ाव और बेहतर भविष्य की आशा भी प्रदान करती है। अस्थायी शिक्षण केंद्र, सुरक्षित विद्यालय, छात्रवृत्तियाँ, डिजिटल शिक्षा और मनोसामाजिक सहायता आपातकाल में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में मदद कर सकती हैं।

माताओं और बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं को सहायता देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएँ, आय अर्जित करने के अवसर, शिक्षा और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, तो परिवार तथा समुदाय संघर्ष से उबरने में अधिक सक्षम बनते हैं।

शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका

अनेक चुनौतियों के बावजूद महिलाओं की पहचान केवल उनकी पीड़ा तक सीमित नहीं है। संघर्ष प्रभावित समाजों में महिलाएँ स्थानीय युद्धविराम के लिए बातचीत करती हैं, संवाद को बढ़ावा देती हैं, मानवाधिकारों के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण करती हैं, मानवीय सहायता प्रदान करती हैं और शांतिपूर्ण समाधान के लिए आवाज उठाती हैं।

उनके अनुभव समुदायों की बुनियादी आवश्यकताओं—भोजन सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, शिक्षा और सामाजिक मेल-मिलाप—को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शांति वार्ताओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि समझौते केवल राजनीतिक और सैन्य हितों तक सीमित न रहें, बल्कि आम लोगों की आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता दें।

शांति अधिक टिकाऊ तब होती है, जब महिलाएँ निर्णय लेने, सुरक्षा योजनाएँ बनाने और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। उनकी भागीदारी केवल औपचारिक नहीं, बल्कि वास्तविक और प्रभावशाली होनी चाहिए।

निष्कर्ष

युद्ध और संघर्ष के बीच महिलाओं की अनकही कहानियाँ हिंसा के विनाशकारी मानवीय परिणामों के साथ-साथ उससे जूझने वाली महिलाओं के असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प को भी उजागर करती हैं। प्रत्येक विस्थापित परिवार, तबाह समुदाय और बाधित बचपन के पीछे कोई महिला आशा को बचाए रखने और भविष्य को दोबारा सँवारने के लिए संघर्ष कर रही हो सकती है।

लेकिन महिलाओं के साहस की प्रशंसा करना उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का विकल्प नहीं हो सकता। सरकारों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों और मानवाधिकारों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। मानवीय सहायता संगठनों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करानी चाहिए और समाज को पीड़ितों के प्रति भेदभाव तथा हिंसा को अस्वीकार करना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को केवल सहायता की जरूरत वाली पीड़ितों के रूप में नहीं, बल्कि अधिकारों, आवाज, कौशल और नेतृत्व क्षमता से संपन्न व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाए।

शांति की वास्तविक कसौटी केवल हथियारों का शांत हो जाना नहीं है। वास्तविक शांति वह है, जिसमें महिलाएँ सुरक्षित रूप से आ-जा सकें, बच्चे विद्यालय जा सकें, परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सकें और समुदाय बिना भय के अपना भविष्य दोबारा बना सकें। जब तक ये परिस्थितियाँ वास्तविकता नहीं बनतीं, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं की अनकही कहानियाँ हमें याद दिलाती रहेंगी कि स्थायी शांति के लिए मानवीय गरिमा, न्याय और समानता की रक्षा करना अनिवार्य है।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य। शैक्षिक स्तंभकार। प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर.

कलयुग में माँ-बाप बूढ़े नहीं, अकेले हो गए...

अरे मेरे मालिक ये कैसा कलयुग आया है — जिसने ममता की गोद दी और सपनों के लिए छाले सहे, आज वही चौखट पर दो मीठे बोल को तरस रहा है

संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक - परिवहन विशेष समाचार पत्र

गीत के मूल बोल — मूल रूप में प्रस्तुत

> अरे मेरे मालिक ये कैसा कलयुग आया है कि जिन माँ-बाप ने अपनी औलाद की हर खुशी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आज वही माँ-बाप अपने ही घर की चौखट पर बैठे किसी अपने के दो मीठे बोल सुनने को तरस रहे हैं...

> बेटा बड़ा हो गया, शहर चला गया, दौलत कमा ली मगर माँ की ममता और बाप की दुआओं का कर्ज़ शायद भूल गया... माँ ने अपनी गोद देकर तुझे सुलाया, खुद भूखी रहकर तेरा पेट भर आया था... बाप के पैरों में छाले थे फिर भी चलता रहा तेरे सपनों के लिए जलता रहा...

> याद रख जिस घर में माँ-बाप की दुआ होती है वहाँ गरीबी भी रहमत बन जाती है और जिस घर से माँ-बाप की आह निकल जाए वहाँ महलों की दौलत भी दिल को सुकून नहीं दे सकती... तू दुनिया की सारी दौलत खरीद सकता है मगर माँ की ममता और बाप की छाँव बाजार में नहीं मिलती...

> आज बेटा कहता है - अब्बा मेरे पास वक्त नहीं, अम्मी मैं बहुत मशरूफ हूँ... लेकिन वही बेटा बचपन में एक खिलौने के लिए घंटों माँ-बाप के पीछे चलता था तब माँ-बाप ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास वक्त नहीं...

तथ्य एक नजर में — गीत का मार्मिक मुद्दा

- मुद्दा: बुढ़ापा नहीं, अकेलापन — माँ-बाप की सबसे बड़ी पीड़ा समय की कमी नहीं, उपेक्षा है

- कारण: शहर, नौकरी, दौलत और व्यस्तता के नाम पर दूरियां

- त्याग: माँ की भूखी गोद और बाप के छालों वाले पैर — बचपन का पूरा जीवन माँ-बाप की कुर्बानी से बना

- परिणाम: जिस घर से माँ-बाप की आह निकले, वहाँ महल भी सुकून नहीं देते

मुख्य बिंदु

- 1. दुआ बनाम दौलत: दुआ से गरीबी रहमत बनती है, आह से महल भी बोझ बन जाते हैं

- 2. वक्त का फर्क: बचपन में माँ-बाप ने खिलौने के लिए कभी वक्त की कमी नहीं कही, आज बेटा कहता है — मेरे पास वक्त नहीं

- 3. बाजार में नहीं मिलता: दौलत खरीदी जा सकती है, ममता और छाँव नहीं

- 4. कर्ज़ जो चुकता नहीं होता: माँ की ममता और बाप की दुआओं का कर्ज़ पैसे से नहीं, वक्त और सेवा से चुकता है।

विस्तृत विश्लेषण

1. चौखट पर बैठी प्रतीक्षा आज का माँ-बाप बूढ़ा नहीं हुआ, वह अकेला हुआ है। उसके पास घर है, छत है, शायद पेंशन भी है — पर नहीं है तो दो मीठे बोल। चौखट पर बैठा वह माँ-बाप अपने बेटे की आवाज़ नहीं, उसके आने की आहट सुनना चाहता है। यह प्रतीक्षा किसी दौलत की नहीं, अपनापन की है।

2. शहर की दूरी, दिल की दूरी बेटा बड़ा हुआ, शहर गया, कमा लिया — यह सफलता है। पर जब सफलता माँ-बाप से दूरी बन जाए, तो वह सफलता अधूरी है। फोन पर 'मैं मशरूफ हूँ' कहना आसान है, पर वही मशरूफियत एक दिन पछतावा बन जाती है।

3. बचपन की याद — उल्टा वक्त गीत की सबसे मार्मिक पंक्ति यही है — बचपन में बेटा खिलौने के लिए घंटों पीछे चलता था, तब माँ-बाप ने कभी नहीं कहा 'वक्त नहीं'। आज बेटा कहता है। यही उल्टा वक्त इस कलयुग की असली तस्वीर है।

4. क्या करना होगा?

- रोज़ एक फोन, हफ्ते में एक मुलाकात — दौलत नहीं, वक्त दीजिए

- माँ-बाप को बोझ नहीं, आशीर्वाद समझिए

- उनकी दुआ को ही अपनी सबसे बड़ी पूँजी मानिए

- समाज को भी अकेले माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी साझा करनी होगी।

संपादकीय टिप्पणी माँ-बाप की दुआ जिस घर में है, वहाँ गरीबी भी रहमत है। और जिस घर से उनकी आह निकली, वहाँ महल भी खाली हैं। इसलिए दौलत कमाइए, पर माँ-बाप का वक्त मत छीनिए।



हिसार में विभिन्न बस्तियों में विजयादशमी उत्सव एवं शस्त्र पूजन, 106 लोगों ने की सहभागिता

हरियाणा हिसार// राजेश सलूजा



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हिसार की विभिन्न बस्तियों एवं शाखाओं में विजयादशमी उत्सव, शस्त्र पूजन एवं पथ संचलन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। केशव बस्ती (पीएलए), सेक्टर-15, हाउसिंग बोर्ड एवं डिफेंस कॉलोनी, अर्बन एस्टेट शाखा, भारत माता शाखा तथा पटेल बस्ती में आयोजित इन कार्यक्रमों में कुल 106 लोगों ने सहभागिता की, जिनमें 31 स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित रहे।

विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवकों द्वारा भव्य पथ संचलन निकाला गया। अनुशासित पंक्तियों में कदमताल करते हुए स्वयंसेवकों ने संगठन और एकजुटता का परिचय दिया। पथ संचलन के दौरान स्थानीय नागरिकों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। इस दौरान वातावरण उत्साहपूर्ण रहा और लोगों ने भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

कार्यक्रमों में वक्ताओं ने विजयादशमी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। शस्त्र पूजन भारतीय परंपरा में शक्ति, साहस और आत्मरक्षा के संकल्प का परिचायक है। शक्ति का उपयोग सदैव समाज की सुरक्षा, राष्ट्रहित और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए।

वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य समाज में अनुशासन, संगठन, सामाजिक समरसता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करना है। पथ संचलन स्वयंसेवकों के अनुशासन, एकजुटता और संगठनात्मक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विजयादशमी का पर्व स्वयंसेवकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने तथा समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आह्वान किया कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को जीवन में अपनाते हुए समाज में एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ किया जाए।

विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में नगर प्रौढ़ कार्य प्रमुख श्री अमरजीत जी, डॉ. नवीन जी, वेदपाल जी तथा पटेल बस्ती के शाखा कार्यवाह श्री श्याम जी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रमों के माध्यम से विजयादशमी के आदर्शों को आत्मसात करने, सामाजिक एकता को मजबूत करने और राष्ट्रसेवा के संकल्प को जीवन में उतारने का संदेश दिया गया।

ट्रेन में रील बनाने वालों सावधान! रेलवे में रीलबाजी और मोबाइल का हुड़दंग अब पड़ेगा भारी

रेलवे की पटरियों से ट्रेन के कोच तक, खतरनाक रीलबाजी और मोबाइल के शोर पर बड़ा एक्शन — जेल तक की नौबत

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया (महाराष्ट्र)

विशेष विश्लेषण — परिवहन विशेष समाचार पत्र



19 अक्टूबर के निर्देशों से मचा हड़कंप

वैश्विक डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर लोकप्रियता की होड़ ने मनोरंजन को व्यापक तो बनाया, पर सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया है।

कुछ सेकंड की रील, हजारों व्यूज और वायरल होने की चाह में अनेक युवा चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होना, रेलगाड़ी से बाहर झूलना, ट्रैक के आसपास खतरनाक गतिविधियां करना अथवा स्टेशन परिसर में जोखिम भरे दृश्य फिल्माना जैसे काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, ट्रेन के भीतर मोबाइल स्पीकर पर तेज आवाज में रील, गाने और वीडियो चलाना भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनता है।

इन दोनों समस्याओं की प्रकृति अलग है, लेकिन केंद्र में एक ही सवाल है — सार्वजनिक सुरक्षा, अनुशासन और दूसरे यात्रियों के अधिकारों का सम्मान।

क्या है 19 अक्टूबर 2026 का अलर्ट ?

19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे के विभिन्न जोनों ने यात्रियों को मोबाइल पर तेज आवाज में संगीत और वीडियो चलाने से रोकने के लिए जागरूकता तथा प्रवर्तन के कदम उठाने की तैयारी की है।

- दक्षिण रेलवे — 6 अक्टूबर 2026 के सर्कुलर से मंडलों को निर्देश: ट्रेनों और रेलवे परिसर में स्पीकर मोड पर संगीत/वीडियो चलाने तथा जोर-जोर से बातचीत करने से होने वाली परेशानी के प्रति यात्रियों को जागरूक किया जाए।

- उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे की ओर से भी ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई के प्रयासों का उल्लेख।

- स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, सूचना संदेश और रेल कर्मचारियों के माध्यम से सचेत करना इस पहल का हिस्सा है।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: उपलब्ध रिपोर्ट को पूरे देश में एक ही दिन जारी हुए किसी एक नए रेलवे बोर्ड आदेश का प्रमाण मानने के बजाय, संबंधित जोनों की कार्रवाई के संदर्भ में पढ़ना अधिक सटीक होगा।

कानूनी पृष्ठभूमि — तिथियां और तथ्य - घटना तिथि / विवरण

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026

राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी — 7 अप्रैल 2026,

राजपत्र में प्रकाशन — 8 अप्रैल 2026

रेलवे बोर्ड सर्कुलर - 23 जून 2026, अधिसूचना सं: एसओ. 3255 (ई) दिनांक 19.06.2026

उद्देश्य 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन, 717 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने की दिशा में कदम

जोनल निर्देश अक्टूबर 2026 में चेन्नई, दक्षिण रेलवे आदि में विशेष जन-जागरूकता और कड़े दिशा-निर्देश पुनः जारी

इस संशोधित नियम के बाद से ही चेकिंग स्टाफ (TTE), रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को रेलवे अधिनियम की संशोधित धाराओं के तहत कार्रवाई का अधिकार मिला है।

धारा 145 और 147 — क्या कहते हैं कानून ?

धारा 145 — उपद्रव मचाना मोबाइल स्पीकर पर लगातार तेज आवाज में रील/गाना/वीडियो चलाना अथवा जोर-जोर से बातचीत कर सहयात्रियों को परेशान करना परिस्थितियों के अनुसार उपद्रव की श्रेणी में आ सकता है। इसके तहत कार्रवाई और संबंधित व्यक्ति को रेलवे परिसर से हटाने की व्यवस्था है।

धारा 147 — अतिक्रमण / बिना अधिकार प्रवेश बिना वैध अधिकार रेलवे परिसर में प्रवेश, रेलवे संपत्ति का दुरुपयोग अथवा वैध निर्देश के बावजूद वहां से न हटना। खतरनाक स्टंट रील के तथ्यों के आधार पर इस धारा का उपयोग हो सकता है, लेकिन हर प्रकार की रील बनाना अपने आप धारा 147 के तहत अपराध घोषित करना सही नहीं होगा।

₹1,000 से ₹5,000 जुर्माना और जेल — क्या समझना जरूरी है ?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक:

- पहली कार्रवाई: ₹1,000 तक का जुर्माना

- चेतावनी के बाद भी उपद्रव जारी रखने पर: ₹5,000 तक के जुर्माने की संभावना

- कुछ परिस्थितियों में: 6 महीने तक की कैद का उल्लेख

> इसका अर्थ यह नहीं है कि मोबाइल पर हर वीडियो देखने वाले पर स्वतः ₹5,000 जुर्माना लगेगा या उसे जेल भेज दिया जाएगा। कार्रवाई कानून, अपराध के तथ्यों, लागू दंड प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार होगी।

सामान्य रूप से ईयरफोन लगाकर वीडियो देखना या संगीत सुनना प्रतिबंधित नहीं है, बशर्ते इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी न हो।

खतरनाक रीलबाजी — जान से बड़ा कोई वायरल नहीं चलती ट्रेन से झूलना, दरवाजे पर असुरक्षित खड़े होकर वीडियो बनाना या ट्रैक पर जोखिम भरी गतिविधि करना कहीं अधिक गंभीर सुरक्षा जोखिम है। इससे संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ रेल परिचालन और दूसरे लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

युवाओं को समझना होगा — सोशल मीडिया पर कुछ क्षणों की लोकप्रियता जीवनभर की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रैक, चलती ट्रेन के दरवाजे और रेलगाड़ी की छत मनोरंजन या स्टंट के स्थान नहीं हैं।

रेलवे कर्मचारी क्या कर सकते हैं ? और यात्री शिकायत कैसे करें ?

- TTE, RPF, GRP अपनी-अपनी वैधानिक शक्तियों और अधिकार-क्षेत्र के भीतर काम करते हैं।

- निर्देश देने का अधिकार होना और मौके पर मनमाना जुर्माना लगाने का अधिकार होना दो अलग बातें हैं। इसलिए कार्रवाई की स्थिति में संबंधित नियम और आधिकारिक प्रक्रिया की जानकारी मांगें।

- शिकायत माध्यम: रेल मदद पोर्टल / ऐप और रेलवे हेल्पलाइन 139

- शिकायत में ट्रेन संख्या, कोच, यात्रा का समय और समस्या का संक्षिप्त विवरण दें।

- तत्काल सुरक्षा खतरा हो तो रेलवे कर्मचारियों या सुरक्षा कर्मियों को तुरंत सूचित करें। यात्रियों को स्वयं उपद्रवी से भिड़ने की आवश्यकता नहीं है।

संपादकीय निष्कर्ष

> रेलवे केवल परिवहन का साधन नहीं, साझा सार्वजनिक जिम्मेदारी भी है। मोबाइल पर तेज आवाज में रील चलाने से बचना, ईयरफोन का इस्तेमाल करना, सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादित आवाज में बातचीत करना और खतरनाक स्टंट से पूरी तरह दूर रहना — सामान्य नागरिक शिष्टाचार के साथ-साथ सुरक्षित रेल यात्रा की बुनियादी शर्तें हैं।

सोशल मीडिया पर लोकप्रियता क्षणिक हो सकती है, लेकिन सुरक्षा और जिम्मेदारी का महत्व स्थायी है।

FCRA Amendment Bill 2026 - विदेशी चंदे पर कसावट, संसद में सियासी घमासान

25,000 NGO रद्द, 15,000 Expired, 14,000 बाकी – क्या है नया नियम?

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष ब्यूरो



FCRA Amendment Bill 2026 पर चर्चा, मुख्य दावे और हकीकत:

1. संसद में क्या हो रहा है? - सत्यापित

- FCRA Amendment Bill 2026 लोकसभा में 25 मार्च 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।

- मानसून सत्र में विपक्ष के भारी विरोध के बाद 12 अगस्त 2026 को इसे 31-सदस्यीय Joint Parliamentary Committee (JPC) को भेज दिया गया है। JPC को विंटर सेशन 2026 के पहले हफ्ते तक रिपोर्ट देनी है।

- इसके साथ ही FCRA Amendment Rules, 2026 22 जून 2026 को नोटिफाई हो चुके हैं, जो लागू भी हैं।

2. प्रमुख बातें - बिंदुवार:

a) गृह मंत्री अमित शाह की कैथोलिक बिशप काउंसिल से मुलाकात और $100 में से $30 वाला दावा: शाह ने कहा - ₹हर $100 में से सिर्फ $30 ही कैथोलिक/क्रिश्चियन संस्थानों में जाता है, बाकी 70% कहाँ जाता है?₹

तथ्य: इस मुलाकात की कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार का आधिकारिक पक्ष JPC में है - पारदर्शिता और end-use accountability। $30/$70 का आंकड़ा विश्लेषक का अपना विश्लेषण/दावा है, सरकारी दस्तावेज में इस रूप में नहीं है।

b) NGO की संख्या: 14,000 NGO बाकी, 25,000 cancelled, 15,000 expire।

तथ्य: यह लगभग सही है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 22,000 registrations cancelled और ~15,000 expired/not renewed हैं।

c) नए नियम क्या हैं? - Rules 2026 के अनुसार (सत्यापित):

- Purpose-Based Registration: पहले broad registration था, अब 105 predefined activities में से चुनना होगा, 5 सेक्टर में - Religious (16), Cultural (18), Economic (19), Educational (22), Social (30)। Religious conversion (Proselytisation) पूरी तरह Banned।

- Geographical Restriction: NGO को बताना होगा कि किस राज्य/UT में काम करेगा। दूसरे राज्य में विस्तार के लिए MHA से Form FC-6F में अनुमति।

- 75% Utilisation Rule: अगली किस्त से पहले पिछली किस्त का 75% खर्च करना जरूरी, फील्ड इन्क्वायरी होगी।

- 5 साल का रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल के लिए शर्तें: पिछले 2 साल में कम से कम ₹10 लाख विदेशी फंड उपयोग, सोशल मीडिया अकाउंट्स, प्रकाशन, वेबसाइट की जानकारी देनी होगी। विदेशी नागरिक सामान्यतः पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे।

- Key Functionary की परिभाषा बढ़ी: Director, Trustee, CEO, Governing Body, HUF का Karta तक शामिल - सबकी ID और व्यक्तिगत जिम्मेदारी।

d) सबसे विवादित प्रस्ताव - Bill में क्या है जो अभी कानून नहीं बना:

- अगर NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन cancel, surrender या renew न होने से खत्म हो जाता है, तो उसकी सारी संपत्ति (चल-अचल) जो विदेशी पैसे से बनी है, वह Designated Authority (सरकार द्वारा नियुक्त) के पास चली जाएगी, और वह उसका प्रबंधन/निपटान करेगी।

- यह प्रावधान अभी कानून नहीं है, JPC में विचाराधीन है।

- विपक्ष - कांग्रेस MP Saleng Sangma, K C Venugopal, अखिलेश यादव आदि ने इसे ₹Draconian₹ बताया और कहा कि यह दशकों पुराने स्कूल, कॉलेज, चर्च, अस्पताल, अनाथालय को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि रिन्यूअल में देरी पर ऑटोमेटिक cessation से अधिकार खत्म हो जाएंगे।

- सरकार का पक्ष (Kiren Rijiju): ₹यह किसी अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट नहीं करता, पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित के लिए है।"

e) ₹Church के नाम पर Mercedes₹ वाला उदाहरण:

यह वीडियो में दिया गया उदाहरण है कि पैसा किस काम के लिए आया, उसी में लगना चाहिए। यह Rules 2026 का मूल उद्देश्य है - end-use verification।

निष्कर्ष: FCRA कानून 1976 में बना, 2010 में संशोधित, 2020 में कड़ा हुआ, अब 2026 में और कड़ा हो रहा है। सरकार का तर्क - विदेशी पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़ा है। विपक्ष का तर्क - यह नागरिक समाज और अल्पसंख्यक संस्थानों पर नियंत्रण है। अंतिम फैसला JPC की रिपोर्ट के बाद विंटर सेशन में होगा।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार: सनी लियोनी ने साइबर जागरूकता को बना दिया "कूल" - @MTV Webbed।



पिंकी कुंडू

सनी लियोनी की MTV Webbed में भागीदारी साइबर अपराध जागरूकता के क्षेत्र में एक अत्यंत प्रभावशाली और रणनीतिक हस्तक्षेप के रूप में उभरती है। शो में उनकी मौजूदगी ने सेलिब्रिटी प्रभाव, युवाओं की अपील और वास्तविक साइबर अपराध घटनाओं पर आधारित नाटकीय प्रस्तुतियों को मिलाकर एक उच्च प्रभावी सार्वजनिक शिक्षा मॉडल तैयार किया। नीचे उनके योगदान का एक विस्तृत, संरचित विश्लेषण प्रस्तुत है, जो शो के दस्तावेज़ित प्रारूप और उद्देश्यों पर आधारित है।

सनी लियोनी, जो युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, ने MTV Webbed की पहुंच और विश्वसनीयता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया—यह शो इंटरनेट के अंधेरे पक्ष को वास्तविक साइबर अपराध घटनाओं की नाटकीय कहानियों के माध्यम से उजागर करने के लिए बनाया गया था। उनकी भागीदारी ने दर्शकों की सहभागिता बढ़ाई, संदेशों को अधिक यादगार बनाया, और युवाओं के बीच साइबर सुरक्षा पर बातचीत को सामान्य किया।

उनकी मौजूदगी ने साइबर जागरूकता को "कूल" बनाया—उपदेशात्मक नहीं।

MTV Webbed का उद्देश्य

यह शो निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ बनाया गया था:

* पहचान चोरी, साइबर बुलिंग, रिवेंज पोर्नोग्राफी, फेक अकाउंट्स और ऑनलाइन शोषण जैसी वास्तविक साइबर अपराध घटनाओं को उजागर करना ड्ड युवाओं को "क्लिक करने से पहले सोचें" जैसे मुख्य संदेश से शिक्षित करना ड्ड प्रत्येक एपिसोड के अंत में साइबर कानून विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के टिप्स देना

सनी लियोनी की भागीदारी ने इन संदेशों को अधिक संबंधित और व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाया।

साइबर जागरूकता में सनी लियोनी की भूमिका

1. सेलिब्रिटी विश्वसनीयता और युवा प्रभाव

सनी लियोनी का विशाल डिजिटल फॉलोइंग है—विशेषकर युवाओं में, जो साइबर बुलिंग, प्रतिरूपण और ऑनलाइन धोखाधड़ी के सबसे अधिक शिकार होते हैं। उनकी मौजूदगी ने:

* उन दर्शकों को आकर्षित किया जो सामान्यतः साइबर सुरक्षा सामग्री नहीं देखते ड्ड ऑनलाइन उत्पीड़न और शोषण पर बातचीत को सामान्य किया ड्ड कहानियों में भावनात्मक गहराई जोड़ी, जिससे संदेश अधिक याद रहे

2. साइबर अपराध कथाओं को मानवीय बनाना

उनसे जुड़े एपिसोड अक्सर इन विषयों पर आधारित थे:

* जुनून प्रेरित साइबर अपराध ड्ड बदले के लिए बनाए गए फेक अकाउंट ड्ड सोशल मीडिया इंटरैक्शन के माध्यम से हेरफेर

इन नाट्य रूपांतरणों ने दर्शकों को समझाया कि ऑनलाइन बातचीत कितनी जल्दी अपराध में बदल सकती है।

3. रूढ़ियों को तोड़ना

एक पूर्व एडल्ट इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मुख्यधारा अभिनेत्री बनने की उनकी यात्रा उन्हें इन विषयों पर एक अनोखी विश्वसनीयता देती है:

* ऑनलाइन उत्पीड़न ड्ड निजी तस्वीरों का दुरुपयोग ड्ड कलंक आधारित साइबर बुलिंग

उनकी आवाज़ प्रामाणिक और संबंधित लगती है।

उनकी भागीदारी का प्रभाव

1. दर्शक संख्या और सहभागिता में वृद्धि

उनके नाम से प्रचारित एपिसोड्स को YouTube और MTV India पर अधिक व्यूज़ मिले। इससे:

* क्लिक थ्रू रेट बढ़ा ड्ड सोशल मीडिया चर्चाएँ बढ़ीं ड्ड साइबर जागरूकता क्लिप्स का व्यापक प्रसार हुआ

2. संदेशों की बेहतर स्मरण क्षमता

सेलिब्रिटी एडवोकेसी पर शोध बताता है कि युवा परिचित चेहरों द्वारा दिए गए संदेशों को अधिक याद रखते हैं। उनकी भागीदारी ने:

* साइबर अपराध की गंभीरता को मजबूत किया ड्ड सुरक्षित डिजिटल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया ड्ड साइबर कानून टिप्स को कम तकनीकी और अधिक उपयोगी बनाया

3. साइबर अपराध रिपोर्टिंग का सामान्यीकरण

शो ने लगातार जोर दिया:

* संदिग्ध ऑनलाइन व्यवहार की रिपोर्टिंग ड्ड हानिकारक सामग्री से आवेगपूर्ण जुड़ाव से बचना ड्ड प्लेटफ़ॉर्म रिपोर्टिंग टूल्स का उपयोग

सनी लियोनी की मौजूदगी ने युवाओं में रिपोर्टिंग से जुड़ी झिझक को कम किया।

4. जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार की ओर सांस्कृतिक बदलाव

उनकी भागीदारी ने योगदान दिया:

* स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा चर्चाओं की स्वीकार्यता बढ़ी ड्ड माता पिता की युवाओं के ऑनलाइन व्यवहार में रुचि बढ़ी ड्ड डिजिटल सहमति, गोपनीयता और ऑनलाइन सीमाओं पर अधिक बातचीत

साइबर अपराध रोकथाम के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

साइबर अपराध इन कारणों से बढ़ता है:

* अज्ञानता ड्ड आवेगपूर्ण ऑनलाइन व्यवहार ड्ड सोशल मीडिया की लत ड्ड रिपोर्टिंग की कमी

सेलिब्रिटी प्रभाव और वास्तविक घटनाओं पर आधारित कहानियों को मिलाकर MTV Webbed ने एक उच्च प्रभावी जागरूकता मॉडल बनाया जो:

* शिक्षित करता है ड्ड सशक्त बनाता है ड्ड जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देता है

सनी लियोनी की भागीदारी केवल एक प्रचार उपस्थिति नहीं थी—यह भारत के साइबर सुरक्षा परिदृश्य में एक सार्थक योगदान था। उनकी मौजूदगी ने:

* साइबर अपराध जागरूकता की पहुंच बढ़ाई ड्ड युवाओं की सहभागिता मजबूत की ड्ड सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित किया ड्ड ऑनलाइन शोषण और रिपोर्टिंग पर बातचीत को सामान्य किया

यह मॉडल—सेलिब्रिटी आधारित, कहानी आधारित साइबर जागरूकता—युवा दर्शकों के लिए सबसे प्रभावी आउटरीच रणनीतियों में से एक है।

परिवहन विशेष समाचार पत्र से जुड़े सभी पाठकों और सहयोगियों के लिए विशेष सूचना

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं की हम अपने चैनल के माध्यम से आपको 1. प्रतिदिन की देश विदेश की जानकारी 2. आपके वह आपके बच्चों के कैरियर, 3. आपके बच्चों के भविष्य से संबंधित ज्ञानवर्धक आवश्यक जानकारिया, 4. आपकी सेहत से जुड़ी सभी उपयोगी जानकारियां 5. शारीरिक बीमारियों से बचने के तरीके 6. धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान विश्व के सभी क्षेत्रों के ज्ञानदाताओं के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हम अपने चैनल द्वारा प्रतिदिन एक घंटे के कार्यक्रम "जनता की पुकार" में आपकी आवाज को विश्व के सामने प्रस्तुत कर सरकार और सरकारी विभागों के साथ माननीय न्यायालयों से उसके उचित हल और उसके प्रति पालिसी लागू करवाने में मध्यांतर का माध्यम बनेंगे। आप सभी से अनुरोध आप के अपने शुरू होने वाले चैनल के माध्यम से अपनी शिकायतें, परेशानियां और अनुभव अन्य सभी से साझा करने के लिए तैयार एवं तत्पर रहे। आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

संजय बाठला
मुख्य संपादक

राज्यपाल एवं रक्षा राज्य मंत्री के उपस्थिति में मना रांची में रावण दहन कार्यक्रम





कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

राची, राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मंगलवार की शाम विजयादशमी के अवसर पर भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में जुटे. रक्षा राज्य मंत्री और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की उपस्थिति में रावण दहन किया गया. इस दौरान पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. वहीं, भव्य आतिशबाजी ने लोगों का दिल जीत लिया. आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरती आतिशबाजी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही.

कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सोने की लंका का दहन किया गया. इसके बाद बारी-बारी से मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के विशाल पुतलों को जलाया गया. पुतलों में आग लगते ही मैदान में मौजूद लोगों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए. रावण के पुतले के दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया. पुतलों से उठती आग की लपटों और आतिशबाजी के नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया.मोरहाबादी मैदान में रावण दहन के दौरान की गई भव्य आतिशबाजी ने समारोह को और आकर्षक बना दिया. आसमान में एक के बाद एक रंग-बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी के नजारे देखकर मैदान में मौजूद लोग रोमांचित हो उठे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने रावण दहन का आनंद लिया. जैसे ही रावण का पुतला आग की लपटों में घिरा, मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा.राज्यपाल संतोष गंगवार ने बताया कि विजयादशमी का पर्व भगवान श्रीराम की ओर से रावण पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में मनाया जाता है. रावण दहन के माध्यम से समाज को अहंकार, अन्याय और बुराई का त्याग कर सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया जाता है. मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम ने इसी परंपरा को जीवंत किया. लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ पर्व मनाया. इस आयोजन के साथ ही राजधानी में दशहरा उत्सव का उल्लास अपने चरम पर पहुंच गया.

कल हमने रावण जला दिया, क्या अपने भीतर का रावण जला दिया? डॉ. विक्रम चौरसिया

परिवहन विशेष समाचार पत्र

तालियाँ बजाकर हम घर लौट आए, पर जीवन का अंधेरा वहीं का वहीं है। क्योंकि पुतला जलाना आसान है, प्रवृत्ति जलाना कठिन है।रावण को सिर्फ अहंकार मत समझिए। उनमें वासना थी, तो संयम भी था। सीता का हरण किया, पर बिना सहमति उन्हें स्पर्श न करने का संकल्प भी निभाया। सीता जीवित मिलीं, यह राम की शक्ति थी। सीता पवित्र मिलीं, यह रावण की भी मर्यादा थी।

उस युग का रावण अपने दस चेहरे सामने रखता था। आज के रावण ने चेहरे छिपा लिए हैं। एक चेहरा मुस्कुराता है, नौ चेहरे भीतर जलते हैं। सामने राम बनता है, पीठ पीछे रावण।

जलते हुए रावण का सवाल आज भी गूँज रहा है तुम में से कोई राम है क्या?

हम पुतला तो जला देते हैं, पर भीतर के छल, कपट, झूठ, मक्कारी, ईर्ष्या, जलनखोरी और स्वार्थ को पालते रहते हैं।

आज भेदभाव चरम पर है। योग्यता से ज़्यादा पहचान चलती है, काबिलियत से ज़्यादा रिश्ता। जाति, धर्म, धन और पद ने इंसान और इंसान के बीच दीवार खड़ी कर दी है।क्या इसी रामराज्य के लिए राम ने युद्ध किया था?जन्म का समय नौ माह तय है, मृत्यु का कोई समय तय नहीं। कोई सौ वर्ष जीता है, कोई जन्म लेते ही चला जाता है। कोई भी नहीं जानता अगली साँस कब आखिरी होगी। फिर भी हममें संवेदना नहीं है।याद रहे, अंत में सब मिट्टी ही होंगे। अमीर की मिट्टी और गरीब की मिट्टी में कोई अंतर नहीं होगा। साथ जाएगा तो केवल व्यवहार, करुणा और मानवता। फिर यह छल, यह स्वार्थ किसके लिए?इस विजयादशमी पर एक संकल्प लीजिए कि सच पर टिके रहेंगे लाभ हो या हानि, झूठ, छल और मक्कारी का त्याग करें।गिराएँ नहीं, उठाएंगे किसी का पैर न खींचें, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएँ। किसी को गिराकर उठना, उठना नहीं होता।सेवा ही धर्म है जितनी सामर्थ्य



है, उतने में ही किसी भूखे, अनाथ और असहाय का सहारा बनें। मानव सेवा ही सच्चा धर्म है, और यह सेवा आखिरी साँस तक चलनी चाहिए।

इंसान को इंसान समझें जाति-धर्म से ऊपर उठकर सोचें। समता, करुणा और मानवता ही सच्चा राष्ट्रधर्म है ,यही सच्चा दशहरा है। यही सच्ची विजयदशमी है।राम कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है। रावण कोई व्यक्ति नहीं, एक वृत्ति है। जिस दिन हमने अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ को हरा दिया, उसी दिन सच्ची विजयादशमी होगी।अपने मन से कहिए आज मैं अपने अहंकार को जलाता हूँ, आज से राम बनने की यात्रा शुरू करता हूँ।

सबको प्यार, सबकी सेवा यही सबसे बड़ा धर्म है।आइए, आज से मानवता को सर्वोपरि रखते हुए, निःस्वार्थ सेवा और समता के पथ पर चलें। यही आने वाली पीढ़ी को दिया गया सबसे बड़ा संस्कार होगा। यही राष्ट्रधर्म है, यही मानवधर्म है।

चिंतक/ मेंटर/ एक्टिविस्ट/ दिल्ली विश्वविद्यालय

सीजेपी के विरोध में 'लाल हिट जनता पार्टी का उदय : सौरभ वार्ष्णेय

सौरभ वार्ष्णेय

देश की राजनीति में विरोध और प्रतिरोध की नई तस्वीर सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अभिजीत दीपके से जुड़ी बताई जा रही कॉकरोच जनता पार्टी के मुकाबले 'लाल हिट जनता पार्टी नाम से एक नए संगठन के सामने आने की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में इस संगठन की पहली सदस्यता बैठक आयोजित की गई, जिसमें शामिल लोगों ने सीजेपी, कांग्रेस और अन्य प्रदर्शनकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि लोकतंत्र में विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए और असहमति का जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए।'लाल हिट जनता पार्टी के प्रमुख और संयोजक अयान भटनागर के बयानों के मुताबिक, इस संगठन का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि सीजेपी और उसके विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना है। उनका दावा है कि संगठन भविष्य की रणनीति तैयार करेगा और विभिन्न स्थानों पर छोटे-बड़े समूहों के माध्यम से अपनी बात रखेगा। उन्होंने सीजेपी को खुली बहस की चुनौती भी दी है। उनके अनुसार, यदि विरोध करने वाले अपने विचारों को लेकर आश्वस्त हैं, तो उन्हें सार्वजनिक चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। यह घटनाक्रम केवल दो संगठनों के बीच टकराव की कहानी नहीं है। इसके पीछे लोकतांत्रिक विरोध, राजनीतिक लामबंदी, जनमत निर्माण और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद हैं। किसी संगठन का विरोध करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन उस विरोध की वैधता और प्रभाव का आकलन उसके नारों से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्यों, तथ्यों और तरीकों से किया जाना चाहिए।लोकतंत्र में असहमति को दबाने के बजाय उसे सुनना और समझना आवश्यक है। किसी सरकारी संस्था, संवैधानिक पदाधिकारी या राजनीतिक दल के फैसलों से असहमति होने पर नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, अपनी बात रखने और सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह, किसी प्रदर्शन से असहमत नागरिकों को भी अपनी राय व्यक्त करने तथा उसके विरोध में शांतिपूर्ण अभियान चलाने का अधिकार है।इस दृष्टि से 'लाल हिट जनता पार्टी का सामने आना विरोध की राजनीति के जवाब में एक दूसरे विचार के उभरने के रूप में देखा जा सकता है। यदि एक समूह किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरे समूह को उस प्रदर्शन की आलोचना करने से रोका नहीं जा सकता। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति इसी बहुलता में निहित है, जहां अलग-अलग विचारों को सामने आने का अवसर मिलता है।लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब वैचारिक असहमति व्यक्तिगत आरोपों, अपमानजनक भाषा और एक-दूसरे को समाप्त करने की राजनीतिक मानसिकता में बदल जाती है। लोकतंत्र में किसी विचार का मुकाबला बेहतर तर्क से होना चाहिए, न कि केवल तीखे नारों और उत्तेजक नामों से। किसी संगठन की लोकप्रियता का वास्तविक आकलन इस बात से होगा कि वह जनता के सामने कौन-से तथ्य रखता है और जनहित के सवालों पर उसका दृष्टिकोण कितना स्पष्ट है।मीडिया रिपोर्टों में सीजेपी से जुड़े लोगों पर अराजकता फैलाने और विदेशी फंडिंग प्राप्त करने जैसे आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। इन आरोपों को गंभीरता से देखा जा सकता है, लेकिन किसी भी आरोप को प्रमाण के बिना स्थापित तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा। यदि किसी संगठन की गतिविधियों, वित्तीय स्रोतों या प्रदर्शन के दौरान उसके आचरण को लेकर संदेह है, तो संबंधित तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता सभी संगठनों के लिए आवश्यक है। जो संगठन जनता के नाम पर आंदोलन करते हैं, उनसे यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे अपने उद्देश्यों, नेतृत्व, वित्तीय संसाधनों और गतिविधियों के संबंध में जवाबदेह रहें। लेकिन यही कसौटी उन संगठनों पर भी लागू होनी चाहिए जो विरोध प्रदर्शनों का प्रतिरोध करने के लिए सामने आते हैं।एक पक्ष पर लगाए गए आरोपों को दूसरे पक्ष की स्वत: निर्दोषता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कानून का शासन इसी सिद्धांत पर आधारित है कि जांच तथ्यों के आधार पर हो, न कि राजनीतिक पसंद और नापसंद के आधार पर। यदि किसी संगठन को लेकर गंभीर शिकायत है, तो सक्षम संस्थाओं को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। आरोपों के आधार पर किसी समूह को दोषी घोषित करना न्यायपूर्ण लोकतंत्र की भावना के विपरीत है।अयान भटनागर ने सीजेपी को खुली बहस की चुनौती दी है। यह पहल अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकती है, बशर्ते बहस का उद्देश्य केवल एक-दूसरे को नीचा दिखाना न होकर जनता के सामने तथ्यों को स्पष्ट करना हो। लोकतंत्र में सार्वजनिक संवाद की संस्कृति कमजोर पड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक और वैचारिक समूह अक्सर विरोधी विचारों को सुनने के बजाय उन्हें पूरी तरह खारिज करने लगते हैं।यदि सीजेपी और 'लाल हिट जनता पार्टी के प्रतिनिधि किसी सार्वजनिक मंच पर आमने-सामने बैठकर अपने विचार रखते हैं, तो जनता को दोनों पक्षों के तर्क समझने का अवसर मिल सकता है। ऐसी बहस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध के कारण, प्रदर्शन की वैधता, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सवाल, राजनीतिक दलों की भूमिका और सार्वजनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं।हालांकि, बहस केवल चुनौती देने से सफल नहीं होती। इसके लिए तथ्यात्मक तैयारी, संयमित भाषा और विरोधी पक्ष को सुनने की इच्छाशक्ति भी आवश्यक है। यदि दोनों समूह पहले से तय निष्कर्षों के साथ मंच पर आते हैं और केवल आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, तो इससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत, प्रमाणों और तर्कों पर आधारित संवाद लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है।अयान भटनागर ने यह भी दावा किया है कि प्रदर्शनों के कारण कारोबारियों का धंधा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित बदसलूकी का मुद्दा भी उठाया। इन शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन व्यापक सिद्धांत स्पष्ट है कि किसी भी आंदोलन के दौरान आम नागरिकों के अधिकारों और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।बाजारों में काम करने वाले व्यापारी, दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक, कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, मरीज और विद्यार्थी किसी भी राजनीतिक विवाद के प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं होते। यदि विरोध प्रदर्शनों के कारण यातायात बाधित होता है, दुकानों का कारोबार प्रभावित होता है या लोगों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है, तो इसका समाधान निकालना जरूरी है।इसका अर्थ यह नहीं कि कारोबार या यातायात में असुविधा का हवाला देकर हर प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाए। शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन प्रदर्शन के लिए उचित स्थान, समय और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा आयोजक कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा की कोई घटना होती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।अयान भटनागर का यह कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फोन कर दें तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ सकते हैं, राजनीतिक लामबंदी की संभावनाओं की ओर संकेत करता है। लेकिन किसी नेता के आह्वान पर भीड़ जुट जाना और किसी विचार को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त होना दो अलग-अलग बातें हैं।भीड़ की संख्या किसी संगठन की वास्तविक सामाजिक स्वीकार्यता का एकमात्र प्रमाण नहीं हो सकती। जनसमर्थन का मूल्यांकन इस बात से भी होना चाहिए कि संगठन कितने समय तक सक्रिय रहता है, समाज के वास्तविक मुद्दों पर क्या योगदान देता है और अपने विचारों को कितनी स्पष्टता से प्रस्तुत करता है।

किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन की विश्वसनीयता उसके काम, व्यवहार और जवाबदेही से बनती है। यदि 'लाल हिट जनता पार्टी वास्तव में सीजेपी की गतिविधियों का वैचारिक प्रतिरोध करना चाहती है, तो उसे अपने उद्देश्यों और कार्ययोजना को स्पष्ट करना होगा।

भुवनेश्वर एयरपोर्ट से 8.5 किलो मारिजुआना जब्त, दूसरे राज्यों के 3 लोग हिरासत में



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: बैंकॉक के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होते ही भुवनेश्वर में महंगे विदेशी गांजे की तस्करी फिर सक्रिय हो गई है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज 8 किलो 500 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना) जब्त किया गया है। इस मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और सीमा शुल्क विभाग ने दूसरे राज्य के तीन लोगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हिरासत में लिए गए तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले, 17 अक्टूबर को भी भुवनेश्वर एयरपोर्ट से DRI और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने 4 किलो 877 ग्राम गांजा जब्त किया था। यह गांजा यात्रियों के बैग में बने गुप्त चैंबर और कुत्तों के भोजन के डिब्बों से बरामद किया गया था। जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1.85 करोड़ रुपये बताई गई थी। उस मामले में चार गैर-ओड़िया यात्रियों को हिरासत में लिया गया था।

बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करों के लिए एक अहम रास्ता बनता जा रहा है। आरोप है कि बैंकॉक और मलेशिया से विदेशी गांजा लाकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में इसकी तस्करी की जा रही है। लगातार हो रही बरामदगी के बाद सुरक्षा और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। DRI और कस्टम विभाग इस नेटवर्क से जुड़े लोगों तथा तस्करी के संभावित संपर्कों का पता लगाने में जुटे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023